RNI.No. — GUJHIN/2012/45192

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा

श्री 1008 महामंडलेश्वर
श्री स्वामी रामानंद दासजी महाराज
श्री रामानंद दास अन्नक्षेत्र सेवा ट्रस्ट, तपोवन आश्रम

स्व. पं. पू.1008 श्री रामानन्द जी
तपोवन मंदिर, मोरा गांव, सूरत

वर्ष-10 अंक: 91 ता. 02 अक्टूबर 2021, शनिवार कार्यालय:114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो। 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com /Suratbhumi.com /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi

100 अरब डॉलर तो सागर में बूंद बराबर हैं–भारत

नई दिल्ली। भारत ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए अमीर देशों को सौ अरब डॉलर का अनुदान गरीब देशों को देना चाहिए.भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियो से लड़ने के लिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद चाहिए. संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इस महीने जलवायु परिवर्तन पर अहम विमर्श होना है. यूएन के सम्मेलन से पहले अमीर देशों पर जलवायु परिवर्तन के लिए अहम वित्तीय कदम उठाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है. 2009 में दुनिया के सबसे धनी देशों ने सालाना सौ अरब डॉलर देने का वादा किया था ताकि गरीब देश, जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, इन चुनौतियों का सामना कर सकें. हालांकि यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ. भारत की प्रतिबद्धता कहां है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा सौ अरब डॉलर से कहीं ज्यादा मदद की जरूरत है. उन्होंने कहा, ये जो सौ अरब डॉलर की बात आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं जलवायु वित्त के नाम पर कर रहे हैं, असल में समुद्र में एक बूंद बराबर हैं. मुझे लगता है कि उनका योगदान कहीं ज्यादा होन चाहिए. वैसे भारत ने अब तक कार्बन उत्सर्जन करने के लिए अब तक कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है. यानी, उसने अब तक नहीं बताया है कि वह किस साल तक देश में कार्बन उत्सर्जन का स्तर शून्य कर लेगा. चीन ने 2060 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का वादा किया है जबकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 50-52 प्रतिशत तक कम करके 2005 के स्तर पर ले जाएगा. सुब्रमण्यन कहते हैं कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अपने ऊर्जा संसाधानों में नवीकरणीय स्रोतों को जोड़ना जारी रखेगा और उद्योगों को भी स्वच्छ ऊर्जा के फायदे उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी

शहर का दम घोंटने के बाद अब आप भीतर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के विरोध में जंतर- मंतर पर प्रदर्शन की मांग करने वाले किसानों (किसान महापंचायत) के रुख पर आपत्ति जताई जो अदालतों में कानूनों की वैधता को चुनौती देने के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचाय संगठन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें या आपके प्रदर्शन से लोग खुश होंगे।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बार कानूनों को अदालतों में चुनौती देने के बाद विरोध करने वाले किसानों को विरोध जारी रखने के बजाय व्यवस्था और अदालतों में अपना विश्वास करना चाहिए। पीठ ने कहा, आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन राजमार्गों को ब्लॉक कर लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले आप शहर के बाहर सड़कों को अवरोध किया और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है।

प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती- सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे

हैं। सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर भी प्रदर्शन करने की मांग के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

महापंचायत संगठन से हलफनामा दायर करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता किसान महापंचायत संगठन से कहा, पहले आप हलफनामा दायर कर बताए कि फिलहाल सीमाओं पर बैठे प्रदर्शकारियों से आपका कोई संबंध तो नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और अटॉर्नी जनरल को देने का भी आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले आप शहर के बाहर सड़कों को अवरोध किया और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है।

सड़कों से प्रदर्शन हटाने के लिए क्या कर रही सरकार

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की 'नाकेबंदी' को हटाने के लिए क्या कर रही है? शीर्ष अदालत ने एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कि सड़कों को हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता।

गुरुवार को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि किसी समस्या का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से किया जा सकता है , लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और यह एक स्थायी समस्या नहीं हो सकती है। पीठ ने कहा, हम पहले ही कानून बना चुके हैं और आपको इसे लागू करना होगा। अगर हम अतिक्रमण करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमने आपके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। कुछ शिकायतें हैं जिनका निवारण किया जाना चाहिए।

अगले एक सप्ताह में 100 करोड़ पहुंचेगा आंकड़ा

वैक्सीन पर 31 दिसंबर तक कस्टम ड्यूटी में छूट

नई दिल्ली। कोरोना टीकाकरण के अभियान में भारत अगले एक हफ्ते में 100 करोड़ लोगों को टीके का आंकड़ा पूरा कर सकता है। देश में करीब 89 करोड़ लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। अगले 11 करोड़ के लिए आठ दिन तय किए गए हैं। इस बीच दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती पर भी टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। बता दें कि टीकाकरण के नौ महीने पूरे होने वाले हैं। देश की 69 फीसदी आबादी को टीके की कम से कम एक और 25 फीसदी को दोनों खुराकें लग चुकी हैं।

टीके की उपलब्धता और कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने उठाया कदम

देश में कोरोना वैक्सीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट को केंद्र सरकार ने तीन महीने और बढ़ा दिया है। यह छूट अब 31 दिसंबर 2021 तक रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे टीके की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में भी कमी आएगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 29 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना में कहा कि कोरोना वैक्सीन पर यह छूट एक अक्तूबर 2021 से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक जारी रहेगी। इससे पहले अप्रैल महीने में सरकार ने तीन महीने के लिए टीकों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी थी। तीन महीने का समय खत्म होने के बाद एक अक्तूबर से कोरोना टीकों के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगना था, लेकिन अब सरकार ने इसकी अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है।

सरकार का मानना है कि आयात शुल्क में छूट से विदेशी टीकों की लागत को कम रखने में मदद करेगी। इसके जरिये देश में बनने वाली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवाक्सिन के टीकों की कमी होने पर इस्तेमाल किया जाएगा।

जमात–ए–इस्लामी पर होगा बड़ा प्रहार, वित्तीय स्रोत को खत्म करने में जुटी एनआईए

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के वित्तीय स्रोत को खत्म करने में जुटी है। इस संबंध में करीब दर्जन भर संदिग्धों से मिले सुराग के आधार पर जांच एजेंसी जल्द ही नए सिरे से छापेमारी कर सकती है। आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ चल रही जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पाकिस्तान से हो रही फंडिंग के अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों ने कहा कि 8 और 9 अगस्त को हुई छापेमारी के दौरान श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा,

कुलगाम, रामबन, डोडा, जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ और राजौरी जिले में काफी अहम जानकारियां सामने आई थीं। संगठन को हो रही फंडिंग और उसके जरिये कट्टरपंथ के प्रसार पर लगाम कसने के लिए जांच एजेंसी व्यापक रणनीति के तहत काम कर रही है। सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के कट्टरपंथियों और उनके समर्थकों के ठिकानों पर नए सिरे से छापेमारी की जाएगी। कट्टरपंथ और आतंक को शह दे रहे लोगों को एजेंसी ने पहले पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर चिह्नित किया है। सूत्रों ने बताया कि एक दर्जन से अधिक जमात-ए-इस्लामी कैडरों और प्रतिबंधित संगठन से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ के दौरान नए सुराग मिले हैं। सभी कड़ियों को खंगाला जा रहा है।

तालिबान राज के बाद चल रहा विशेष अभियान

जांच एजेंसी अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से कट्टरपंथ के खिलाफ विशेष तौर पर अभियान चला रही है। कई अन्य एजेंसियां संभावित खतरो के मद्देनजर इनपुट साझा करके कार्रवाई में जुटी हैं। सूत्रों ने कहा, एक तरफ घाटी में घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को मार गिराने का अभियान सुरक्षाबलो द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ घाटी के अंदर मौजूद आतंकियों को शह देने वाले कट्टरपंथी संगठनों पर शिकंजा कसने के लिए ताबतोड़ कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं।

दिल्ली–एनसीआर में अगले तीन दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान

नई दिल्ली। देश के कुछ भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर भारत समेत दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर आंध्रप्रदेश, ओडिशा बंगाल समेत आसपास के राज्यों पर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन यानी तीन अक्तूबर तक तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण क्षेत्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में तीन अक्तूबर तक पानी गिरने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, बिहार आंध्रप्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शुक्रवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 1 अक्तूबर से तीन अक्तूबर के बीच मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश का दौर थम जाएगा।

गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में अगले कुछ दिन तक हल्की बारिश की संभावना के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली-एनसीआर में अधिक्तम तापमान करीब 34 डिग्री रहने की संभावना है तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास है।

दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल बेहतर मानसून के कारण दिल्ली में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई है। अब तक 1170.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है,

चीन को भारत का दो-टूक जवाब- ड्रैगन के कारण ही एलएसी पर अशांति, अब भी सीमा पर सैनिक-हथियार बढ़ा रहा

नई दिल्ली। भारत ने एलएसी पर गतिरोध को लेकर चीन पर एक बार फिर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। भारत ने कहा कि चीन के भड़काऊ व्यवहार, यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने की कोशिश के चलते पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगते इलाकों में शांति भंग हुई है। भारत ने कहा कि चीन सीमावर्ती इलाकों में लगातार सैनिकों और सैन्य साजो-सामान की तैनाती कर रहा है। इसी की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को एलएसी पर उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम करेगा। साथ ही पूरी तरह से द्विपक्षीय समझौतों और

चीन के भड़काऊ व्यवहार, यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने की कोशिश के चलते पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगते इलाकों में शांति भंग हुई है। भारत ने कहा कि चीन सीमावर्ती इलाकों में लगातार सैनिकों और सैन्य साजो–सामान की तैनाती कर रहा है।

प्रोटोकॉल का पालन करेगा। चीन ने हाल में आरोप लगाया है कि दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण नई दिल्ली द्वारा आगे बढ़ने की नीति का अनुसरण करना और चीनी क्षेत्र पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना है। इसके जवाब में भारत की प्रतिक्रिया आई है। बागची ने कहा कि भारत ने कुछ दिन पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। साथ ही ऐसे बयानों को खारिज कर दिया, जिनका कोई आधार नहीं है। बागची ने कहा कि चीनी पक्ष की ओर से बड़ी संख्या में सैनिकों के जमावड़े और यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयास के परिणामस्वरूप पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति प्रभावित हुई। बागची ने कहा कि चीन सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों को तैनात करना जारी रखे हुए है। यह चीनी कार्रवाइयों के जवाब में था कि हमारे सशस्त्र बलों को इन क्षेत्रों में उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के सुरक्षा हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दुशांबे में एक बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा चीनी समकक्ष को दिए संदेश का भी जिक्र किया। बागची ने बताया कि जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में चीनी विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में जोर देकर कहा था कि चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम करेगा। साथ ही द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करेगा।

8546 करोड़ रिश्वत देने का आरोप, कहा- कानूनी शुल्क में पेशेवरों को दी रकम भी शामिल

नई दिल्ली। अमेजन ने 2018-20 तक भारत में कानूनी शुल्क के रूप में 8,546 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की रिपोर्ट पर बृहस्पतिवार को सफाई पेश की। कंपनी ने बताया कि इस राशि में पेशेवरों को दिया गया शुल्क भी शामिल है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि अमेजन ने भारत में कानूनी मामलों में सहूलियत पाने के लिए अधिकारियों को बड़ी मात्रा में रिश्वत खिलाई है। सूत्रों के अनुसार, अमेजन ने 28 सितंबर को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में बताया कि कानूनी शुल्क में 8,546 करोड़ खर्च किए जाने की रिपोर्ट सही नहीं है और इसमें कई गलतफहमियां हैं। यह राशि कानूनी और पेशेवर शुल्क के रूप में खर्च की गई। गौरतलब है कि रिश्वत मामले में अमेजन आंतरिक जांच भी करा रहा है और मामले का खुलासा होने के बाद उसने अपने मुख्य कानूनी सलाहकार को छुट्टी पर भी भेज दिया था।

ऐसे खुला था मामला

रिश्वतखोरी का मामला द मॉर्निंग कांटेक्स्ट समाचार पत्र की रिपोर्ट के बाद चर्चा में आया था। इस रिपोर्ट में अमेजन के

वकीलों की तरफ से देश में कंपनी के कानूनी मुद्दे सुलझाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का दावा किया गया था। इसके बाद अमेजन ने इस मामले में तत्काल जांच शुरू करने की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि वह इन आरोपों को गंभीरता से ले रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उचित कार्रवाई करेगी। अमेजन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने जांच शुरू करते हुए अपनी कानूनी टीम के एक वरिष्ठ कारपोरेट वकील को छुट्टी पर भेज दिया है और बाहर से सेवाएं दे रहे एक अन्य वकील को हटा दिया है।

क्यों दी गई रकम, इसकी हो सीबीआई जांच : कैट

कैट ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था। साथ ही अमेरिकी सिक्युरिटीज व एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को भी पत्र लिखकर जांच कराने का आग्रह किया था। कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं इस कथित रिश्वतखेरी का अमेजन के खिलाफ चल रही कई तरह की सरकारी जांच से तो कोई संबंध नहीं है। भारतीय ई-कॉमर्स बाजार और खुदरा व्यापार को अनुचित प्रभाव, ताकत के दुरुपयोग और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत से बचाने के लिए यह कदम उठाए जाना चाहिए।

लगातार विवादों में ई-कॉमर्स कंपनी

बाजार में एकाधिकार बनाने के लिए अमेजन निष्पक्ष व्यापार नियामक और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच का सामना कर रही है। अमेजन फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बीच करीब 24 हजार करोड़ के प्रस्तावित सौदे के खिलाफ भी अदालत में गई थी।

सार समाचार

महाराष्ट्र सरकार बारिश से प्रभावित मराठवाड़ा के किसानों को तुरंत राहत दे: फडणवीस

नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को व्यक्तिगत पंचनामा का इंतजार किए बिना मराठवाड़ा में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए। फडणवीस ने नागपुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि राज्य की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार द्वारा बाढ़ और बारिश से प्रभावित कोकंण, पूर्वी विदर्भ और अन्य क्षेत्रों के किसानों के लिए पूर्व में घोषित राहत पैकेज अब तक नहीं पहुंचाया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने कहा, ''वर्तमान परिस्थितियों में, दिखाई देने वाले नुकसान के आधार पर प्रारंभिक सहायता प्रदान की जा सकती है और व्यक्तिगत पंचनामों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि पंचनामा की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन सरकार को तत्काल राहत की घोषणा करने के बारे में सोचना चाहिए।'' फडणवीस ने कहा कि वह रविवार से मराठवाड़ा के प्रभावित जिलों का दौरा शुरू करेंगे जिसकी शुरुआत वाशिम से होगी और इस दौरान उनके साथ पार्टी नेता प्रवीण दारेकर भी होंगे।

दिल्ली में न्यूनतम तापमान रहा 26.5 डिग्री सेल्सियस, बूंदाबांदी होने का अनुमान

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को बारिश हुई। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, हवा में आर्द्रता का स्तर 80 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ ही दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आईएमडी ने बारिश होने के मद्देनजर शहर के लिए 'ग्रीन अलर्ट' जारी किया है। 'ग्रीन अलर्ट' का मतलब है सब सही है। 'येला अलर्ट' का मतलब है बेहद खराब मौसम, साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि मौसम इतना खराब हो सकता है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। वहीं, 'ऑरेंज अलर्ट' सड़क और नालों के बंद होने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ आवाजाही में व्यवधान की आशंका के साथ बेहद खराब मौसम के लिए चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है।

बिहार समेत समूचे पूर्वी, पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रधानमंत्री के मन में बड़ा स्थान: केंद्रीय मंत्री

इंदौर (मध्य प्रदेश)। बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार इस राज्य को शुरुआत से ही खास तवज्जो देती रही है और समूचे पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत बड़ा स्थान है। बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर चौबे ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ''(केंद्र सरकार द्वारा) बिहार को शुरुआत से ही खास तवज्जो दी जाती रही है। प्रधानमंत्री ने बिहार को वर्ष 2015 में 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया था जो राज्य के विकास में जमीनी स्तर पर काम आया।'' बिहार से ही ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री के मन में बिहार समेत समूचे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बहुत बड़ा स्थान है। जब तक इन इलाकों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा।'

मानसून के बाद मध्य प्रदेश में छह बाघ अभयारण्य पर्यटकों के लिए फिर से खुले

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून में तीन महीने तक बंद रहने के बाद शुक्रवार को छह बाघ अभयारण्य पर्यटकों के लिए फिर से खुल गए। प्रदेश के एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सहित छह बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र को शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे से आगंतुकों के लिए खोल दिया गया। उन्होंने बताया, ''बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों को मानसून के दौरान बंद कर दिया जाता है क्योंकि यह बाघों का प्रजनन का मौसम होता है।' अधिकारी ने बताया कि बारिश के कारण अभयारण्य में रास्ते वाहन चलने योग्य नहीं रहते हैं और वन्यजीवों के लिए इलाके में बुनियादी ढांचे जैसे घास के मैदानआदि विकसित किए जाते हैं।

अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान शाहीन में तब्दील हुआ: मौसम विभाग

मुंबई। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार सुबह चक्रवाती तूफान 'शाहीन' में तब्दील हो गया और शाम तक इसके ' गंभीर चक्रवाती तूफान' में परिवर्तित होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी प्रकोष्ठ ने बताया कि यह तूफान प्रणाली भारतीय तट से दूर जा रही है। आईएमडी ने बताया, '' पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बना चक्रवाती तूफान शाहीन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम- उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और उत्तरी अरब सागर के मध्य हिस्से में यह पहुंच रहा है।'' मौसम विभाग ने बताया, ''अगले 12 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर पश्चिम- उत्तर पश्चिम में बढ़ने और अगले 36 घंटे में मकरान तट (पाकिस्तान) से टकराने की संभावना है। इसके बाद यह दोबारा पश्चिम- दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा और ओमान की खाड़ी में ओमान तट की ओर बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगा।'' चक्रवाती तूफान शाहीन, चक्रवाती तूफान गुलाबके अवशेषों से बना है, जो 26 सितंबर को पूर्वी तट से टकराया था।

हरीश रावत की केंद्र को चेतावनी, पंजाब की बहुमत की सरकार को गिराने की कोशिश न करें

देहरादून। (एजेंसी)।

कांग्रेस महासचिव और पंजाब में पार्टी मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वह पंजाब की बहुमत की सरकार को गिराने की कोशिश न करें। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी की बातचीत आगे बढ़ी है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में रावत ने कहा कि चन्नी दलित मुख्यमंत्री हैं और सभी पार्टियों को उनका सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं भाजपा की केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि पंजाब की बहुमत की सरकार को गिराने की कोशिश न करें।'

रावत ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी है जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बहुत सारे अच्छे कदम उठा रही है जिसमें हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा, बालू पर लगा नियंत्रण भी हटाया जाएगा। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू के बीच तनातनी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि समस्या का कोई न कोई समाधान निकल आएगा और दोनों नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ी है। रावत ने अमरिंदर सिंह को आगाह किया कि वह भाजपा का मुखौटा न बनें। उन्होंने कहा कि वह कैप्टन के उस बयान से हैरान हैं जिसमें उन्होंने अपने 'अपमान' की बात की है।

उन्होंने कहा, 'अमरिंदर सिंह से उम्मीद थी कि वह चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस और सोनिया जी को मजबूती देंगे।' उन्होंने कहा कि वह 1980 से कांग्रेस से जुड़े हैं और तीन बार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और दो बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा, 'अपमान की बात कहने से पहले उन्हें (अमरिंदर सिंह) कांग्रेस के उन नेताओं से तुलना कर लेनी चाहिए थी जिन्हें उनसे काफी कम मिला।'

रावत ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक तब बुलाई गई जब 43 विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने शुरू किए और इस बैठक की सूचना उन्होंने स्वयं अमरिंदर सिंह को दी थी। इस संबंध में उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि अमरिंदर ऐसे बयान कहीं किसी दबाव में तो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कैप्टन को भाजपा के जाल में न फंसने के प्रति आगाह भी किया। हांलांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस अमरिंदर सिंह की वापसी के लिए कोई प्रयास करेगी, रावत ने इस मसले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

विषम मौसम के कारण देश में जून से अगस्त के बीच 400 से अधिक लोगों की मौत

मुंबई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण विषम मौसम की घटनाओं में पिछले तीन महीने में देश भर में कम से कम 435 लोगों की मौत हो गयी। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जुटाये गये आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है। आंकड़ों के अनुसार इनमें आकाशीय बिजली गिरने से जान गंवाने वाले 240 लोग शामिल हैं।यह संख्या कुल हताहतों का 50 फीसदी से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले तीन माह (जून से अगस्त) में देशभर में विषम मौसमी घटनाओं में हुई मौतों में से एक तिहाई मौत महाराष्ट्र में हुई।

इसमें कहा गया है कि तीन महीने मेंखराब मौसम की वजह से जून में 109 लोगों की, जुलाई में 301 लोगों की जबकि अगस्त में कुल 25 लोगों की मौत हुयी है। मॉनसून के दौरान खराब मौसम में आकाशीय बिजली गिरना, भारी बारिश (बाढ़ का कारण) तथा अन्य घटनायें शामिल हैं। महाराष्ट्र में इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि इस साल जुलाई में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण आयी बाढ़ एवं भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 213 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के कोंकण क्षेत्र के अलावा कोल्हापुर और सांगली जिले में बड़े पैमाने पर क्षति हुई। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि सितंबर महीने में होने वाली मौत के आंकड़ों को एकत्र किया जा रहा है।

एमएसपी पर धान की खरीद को खत्म करने की साजिश की जा रही : रणदीप सिंह सुरजेवाला

चंडीगढ़। (एजेंसी)।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने धान की खरीद को 11 अक्टूबर तक स्थगित करने के निर्णय पर शुक्रवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद को खत्म करने की स्पष्ट साजिश है। केंद्र ने भारी बारिश की वजह से फसल के पकने में विलंब के चलते बृहस्पतिवार को पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद 11 अक्टूबर तक स्थगित कर दी थी। फसल की खरीद राज्य की एजेंसियों के साथ केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।

हरियाणा की मंडियों में धान पहुंचने का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा, ''लाखों क्विंटल धान 20 सितंबर से ही मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। तब से 11 दिन गुजर गए हैं लेकिन अब तक हरियाणा में एमएसपी पर एक भी दाना नहीं खरीदा गया है।'' कांग्रेस नेता ने एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा में खुले आसमान के नीचे मंडियों में 20 लाख क्विंटल धान पड़ा है। उन्होंने कहा, ''अंबाला में मंडियों में 4.5 लाख क्विंटल धान पहुंच चुका है। कुरुक्षेत्र में 5.5 लाख क्विंटल, यमुनानगर में 2.25 लाख क्विंटल, कैथल में दो लाख क्विंटल और करनाल में 1.75 लाख क्विंटल फसल मंडियों में पड़ी है।''

सुरजेवाला ने कहा कि हजारों किसान सरकार के खरीद शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं और इस स्थिति में किसान कहां जाएंगे। खरीद स्थगित करने के निर्णय के बारे में कांग्रेस नेता ने कहा, ''यह एमएसपी पर धान की खरीद को खत्म करने की स्पष्ट साजिश है। हरियाणा में धान 20 सितंबर से मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया था और अगर सरकार इसे 11 अक्टूबर तक नहीं खरीदेगी तो फिर यह एमएसपी को खत्म करने की साजिश नहीं है तो फिर क्या है?'' उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार एमएसपी को खत्म करना तथा किसानों को खुले बाजार की दया पर छोड़ना चाहती है।

सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकारों का ''किसान विरोधी'' चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा में धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि हरियाणा में एक अक्टूबर से धान और बाजरा की खरीद शुरू की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की भाजपा-जजपा सरकार हाल में हुई भारी बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान के लिए 15 दिन के भीतर किसानों को मुआवजा प्रदान करे।

गोवा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, संजय राउत बोले- 22-25 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

पणजी। (एजेंसी)।

गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिवसेना गोवा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि पिछले 25 सालों से हम गोवा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं और हमारे खाते में 2-3 सीटें आती रही हैं। इस बार हमनें(शिवसेना) तय किया है कि गोवा में हम 22-25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी ताक़त से यहां चुनाव लड़ेंगे।

इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि जब गोवा में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है तो हम तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के हैं। ऐसे में हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं ? वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शिवसेना प्रदेश की 40 में से 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी शिवसेना

राउत ने कहा था कि अगर शिवसेना गोवा विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो यहां पर महाराष्ट्र शासन का मॉडल अपनाया जाएगा। हालांकि शिवसेना का अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं हुआ है।

जिलाधिकारी ने मण्डलीय रबी गोष्ठी की तैयारियों की समीक्षा बैठक की

संवाददाता लक्ष्मीकांत पाण्डेय।

जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी(2021-22) की तैयारी हेतु समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने अच्छादन की प्रतिशत की जानकारी लेते हुए मिनी लक्ष्य तथा खरीफ के लिए कोई फर्टीलाइजर आदि की आवश्यकता आदि तो नहीं है कि समीक्षा करते हुए उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या आदि नहीं आनी चाहिए, जिप्सम आदि की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। कीटनाशक, वायोपेस्सीडाइज आदि की गुणवत्ता व निर्धारित मूल्य सही रहे, इसके लिए निरंतर अभियान चलाकर छापेमारी आदि की कार्यवाही करते रहे। फसली ऋण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका भुगतान किसानों को क्यों नहीं किया गया, उस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा यूनिवर्सल कम्पनी के खिलाफ पत्र लिखने के निर्देश दिये है तथा उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया है कि यथाशीघ्र क्लेम का भुगतान सुनिश्चित कराये। पराली जलाने वाले क्षेत्रों का चिन्हॉकन उसके साथ गोष्ठी कर ये बताये कि कोई पराली न जलायें। अधिशाषी अभियंता बेलन नहर को निर्देशित किया कि नहरों में पानी की स्थिति ठीक होना चाहिए तथा ससमय सिल्ट सफाई आदि करना सुनिश्चित करें। राजकीय नलकूप के अधिशाषी अभियंता को निर्देशित किया है कि नलकूप खराब होता है, तो 2 दिनों के अंदर उसे ठीक करा लिया जाये। जैविक खेती की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा किनारे कितने गांवों में किया जाता है तथा उसकी क्या स्थिति है, उसे और मजबूत ढंग से कराया जाये। कृषि यंत्रों की समीक्षा करते हुए कहां कि कितने आवेदन प्राप्त हुए। उसके सापेक्ष कितना वितरण किया गया, की जानकारी ली तथा उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता कत्तई क्षम्य नहीं होगा। इसकी मानीटरिंग सुचारू रूप से निरंतर करते रहे। बैठक में उप निदेशक कृषि श्री विनोद कुमार, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री इन्द्रजीत यादव सहित सभी सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आखिर कहां हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह? महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहीं यह बड़ी बात

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

क्या देश छोड़कर भाग चुके हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह? आखिर एजेंसियां क्यों नहीं बता पा रही कि परमबीर सिंह कहां है? उनके रूस जाने की खबर कहां से आई? यह तमाम सवाल परमबीर सिंह को लेकर पूछे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह रूस भाग गए हैं लेकिन इतनी आसानी से वह कैसे जा सकते हैं। इसको लेकर भी संशय है। इन सबके बीच परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसको लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जानकारी दी। दिलीप वलसे पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी सूचना हैं कि सिंह ने देश छोड़ दिया है। लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है।

गृह मंत्री ने क्या कहा

अपने बयान में राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी होने के नाते विदेश यात्रा पर प्रतिबंध है। आप सरकार की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। फिर भी वह चले गए, तो यह अच्छी बात नहीं है। पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार सिंह को खोजने के लिए केंद्र के संपर्क में है। सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस साल मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने और होमगार्ड में स्थानांतरित होने के कुछ दिनों बाद सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि देशमुख पुलिस अधिकारियों से मुंबई में रेस्तरां और बार मालिकों से पैसे लेने के लिए कहते थे।

राज्य सरकार ने सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल का एक सदस्यीय आयोग गठित किया था। आयोग ने सिंह को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उसके बाद आयोग ने सिंह के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था। सिंह पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं। वह इस साल अप्रैल में एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) कानून के तहत एक मामले का भी सामना कर रहे हैं।

अवैध निवासी 2050 तक असम में सत्ता हथियाने का खाका तैयार कर रहे हैं: सरमा

गुवाहाटी। (एजेंसी)।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया कि ''अवैध निवासियों'' ने 2050 तक राज्य में सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक खाका तैयार किया है और धीरे-धीरे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वे बहुमत हासिल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दरांग जिले में गोरुखुटी में कथित अतिक्रमणकर्ता सत्ता पर कब्जा करने की इस साजिश का हिस्सा हैं। गोरुखुटी में अतिक्रमण करने वाले लोगों को हटाने के लिए पिछले हफ्ते चलाए अभियान में दो दिनों में दो नागरिकों की मौत हो गयी थी। बहरहाल, सरमा ने उन्हें मुस्लिम बताने से इनकार करते हुए दावा किया कि केवल एक वर्ग ऐसी गतिविधियां चला रहा है।

सरमा ने धेमाजी में कहा, ''हमें 'इस्लामिक' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि असम के मुस्लिम उनके साथ शामिल नहीं हैं। यह एक वर्ग की विचारधारा है। वे (अतिक्रमणकर्ता) चरणबद्ध तरीके से नए निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत हासिल करने का खाका तैयार करते हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं था और इस पर (खुफिया और अन्य एजेंसियों से) कागजात और रिपोर्टों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैंने इसे देखा है।'' उन्होंने कहा कि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ये ''अवैध निवासी'' सिपाझर, बोरखोला और लुमडिंग विधानसभा क्षेत्रों में 2026 तक जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति में बदलाव लाकर वहां बहुमत हासिल करने की कोशिश में हैं। गोरुखुटी सिपाझर निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। उन्होंने दावा किया, ''इनकी 2050 तक राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने की योजना है।''

उन्होंने कहा कि बाटाड्रोबा, बारखेत्री और मंगलदई में जनसांख्यिकीय बदलाव हुए जैसा कि इस साल विधानसभा चुनावों में देखा गया जिसके कारण विपक्षी दल कांग्रेस ने उन तीन सीटों पर जीत हासिल की थी जो पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास थी। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि गोरुखुटी से हटाए गए 10,000 लोगों में से करीब 6,000 के नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मसौदे में नहीं हैं। सरमा ने कहा, ''जो गोरुखुटी में लंबे समय से रह रहे हैं और जिनके नाम एनआरसी में हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे।

सार समाचार

पाकिस्तान: पेशावर में सिख हकीम की गोली मारकर हत्या

पेशावर में बृहस्पतिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक जानेमाने सिख हकीम की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय हकीम सरदार सतनाम सिंह (खालसा) अपने क्लीनिक पर थे तभी हमलावर उनके केबिन में घुस गये और गोलियां चला दीं। पुलिस ने कहा कि सिंह को चार गोलियां लगीं और उनकी मौके पर मौत हो गयी। हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे। पेशावर में सिख समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य सिंह चरसद्दा रोड पर क्लीनिक चलाते थे। हालांकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने खबर दी है कि सिंह को घायल अवस्था में खैबर पख्तूनखवा प्रांत की राजधानी के लेडी रीडिंग अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि सिंह एक दिन पहले ही हासन अब्दाल से पेशावर पहुंचे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर ली। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। किसी ने हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। पेशावर में करीब 15,000 सिख रहते हैं जिनमें अधिकतर कारोबार करते हैं और कुछ फार्मेसी चलाते हैं। पुलिस आतंकवाद की संभावना समेत विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं नजला बांडेत रमजाने, जल्द मंत्रिमंडल गठन करने के निर्देश

ऑस्टिन (अमेरिका)। अरब देश ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने बुधवार को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्राध्यापिका नजला बांडेत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। राष्ट्रपति द्वारा अपने पूर्व अधिकारी को बर्खास्त किए जाने के बाद और 25 जुलाई को संसद भंग कर कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेने के बाद से, देश में प्रधानमंत्री का स्थान रिक्त था। अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए रमजाने को इस पद पर नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द अपने मंत्रिमंडल का गठन करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति के इस कदम की संसद में भारी आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है कि यह देश में लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही राष्ट्रपति ने इसे देश को आर्थिक और सामाजिक संकट से बचाने के लिए जरूरी कदम बताया है और साथ ही ट्यूनीशिया और ट्यूनीशिया की महिलाओं का सम्मान करार दिया है।

अफगानिस्तान को लेकर कई मुद्दों पर समान है भारत और अमेरिका की सोच: जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से संबंधित कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका की सोच एक समान है जिसमें आतंकवाद के लिए अफगान भूमि के संभावित उपयोग को लेकर चिंताएं भी शामिल हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि कई ऐसे पहलू हैं जिनपर दोनों के विचार समान नहीं हैं। जयशंकर अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तालिबान शासन को मान्यता देने संबंधी किसी भी प्रश्न का निदान दोहा समझौते में समूह द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के आधार पर किया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम इनमें से कई मुद्दों पर सैद्धांतिक स्तर पर समान सोच रखते हैं। इसमें निश्चित रूप से आतंकवाद शामिल है। अफगान भूमि का आतंकवाद के लिए उपयोग हम दोनों को बहुत दृढ़ता से महसूस होता है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात की थी तो इस पर चर्चा की गई थी।'

सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली पाक के नापाक इरादों की पोल, चोरी-छुपे श्रीनगर से 155 किलोमीटर की दूरी पर बनाया रनवे

चीन जहां नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिविधियां लगातार तेज कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से भारत की कश्मीर पर नापाक नजरें गराए बैठा रहता है। पाकिस्तान श्रीनगर से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्कर्दू एयरबेस को अब अपग्रेड कर रहा है। इस बात का खुलासा सेटेलाइट की तस्वीर से हुआ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्कर्दू एयरबेस पर दूसरे रनवे का काम लगतभग पूरा कर दिया है। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर जेएफ-17 लड़ाकू विमानों की स्कॉडन को तैनात किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा की सेटेलाइट तस्वीर में बताया गया है कि स्कर्दू एयरबेस पर दूसरे रनवे का काम काफी हो चुका है। मई 2020 में डेट्रेस्फा ने ही इस एयरबेस के अपग्रेडेशन को लेकर पहली बार जानकारी दी थी। पाकिस्तान वायुसेना स्कर्दू एयरबेस के संचालन में चीन का भी साथ लेती है। इस एयरबेस पर चीन के कई एयरक्रॉफ्ट भी देखे जा चुके हैं।

रणनीतिक रूप से है बेहद महत्वपूर्ण

पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके रणनीतिक रूप से पीओके के स्कर्दू में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयरपोर्ट का बड़ा महत्व है। यहां से श्रीनगर और लेह की दूरी महज 200 किलोमीटर है। यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की चौकस निगाहों से बच पाना संभव नहीं है।

उत्तर कोरिया ने किया चौथा मिसाइल परीक्षण, दक्षिण कोरिया पर बना रहा है दबाव

सियोल। (एजेंसी)।

उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक नव विकसित विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल में किया गया यह उसका चौथा मिसाइल परीक्षण है। उत्तर कोरिया ने करीब छह महीने बाद सितंबर में एक बार फिर मिसाइल परीक्षण शुरू किया था, हालांकि वह दक्षिण कोरिया के साथ कुछ शर्तों पर बातचीत को तैयार है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंधो में ढील और अन्य रियायतें देने के लिए राजी कर पाए।उत्तर कोरिया की आधिकारिक 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने कहा कि विमान-रोधी मिसाइल परीक्षण ''विमान-रोधी मिसाइल प्रणाली के विभिन्न संभावित अध्ययन एवं विकास की दिशा में बहुत व्यावहारिक महत्व रखता है।''

केसीएनए ने कहा कि परीक्षण का लक्ष्य लॉन्चर, रडार और युद्ध कमांड वाहन के संचालन की व्यवहारिकता के साथ-साथ मिसाइल की युद्धक क्षमता की पुष्टि करना था। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका आम तौर पर उत्तर कोरियाई मिसाइल के परीक्षण के तुरंत बाद सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के परीक्षण के संबंध में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। यह दर्शाता है कि यह कोई प्रमुख परीक्षण नहीं था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शांति स्थापित करने के लिए अक्टूबर के शुरू में दक्षिण कोरिया के साथ 'हॉटलाइन' बहाल करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने वार्ता के अमेरिकी प्रस्ताव को यह कहकर फिर से ठुकरा दिया कि यह उत्तर कोरिया के खिलाफ शत्रुता को छुपाने का अमेरिका का ''कुटिल तरीका'' है। उन्होंने एक बार फिर दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और अन्य घटनाक्रम के लिए अपने ''दोहरे व्यवहार के दृष्टिकोण'' और ''शत्रुतापूर्ण नजरिए'' को छोड़ने की मांग की। वहीं, दक्षिण कोरिया ने कहा कि वह कई लंबित मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक 'हॉटलाइन' की बहाली को तैयार है।

खत्म हुआ जापान में आपातकाल, कोविड-19 संबंधी नियमों में दिए जाएंगे ढील

तोक्यो। जापान छह महीनों से अधिक समय बाद पहली बार कोरोना वायरस संबंधी आपात स्थिति से पूरी तरह बाहर आ गया है। संक्रमण के मामले कम होने के कारण देश ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोविड-19 संबंधी नियमों में धीरे-धीरे ढील देना शुरू कर दिया है। तोक्यो के व्यस्त शिंगावा ट्रेन स्टेशन पर मास्क पहने हुए यात्री अपने-अपने काम पर जाते हुए दिखे। इनमें से कुछ लोग महीनों बाद कार्यालयों में जा रहे थे। तोक्यो समेत आधे से अधिक देश में लगा आपातकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो गया। पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के बाद यह फैसला लिया गया है। महामारी के मामलों में कमी आने के कारण जापान की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दबाव कम हुआ है। निवर्तमान प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने लोगों का उनके धैर्य और सहयोग के लिए आभार जताया और वायरस रोधी मूल उपायों का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा, ''एक बार फिर मैं आपका सहयोग मांगता हूं ताकि हम सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी दिनचर्या में लौट सकें।'' आपातकाल की स्थिति हटाए जाना कुछ लोगों के लिए एक नयी शुरुआत है। अकीफुमी सुगीहारा ने कहा कि वह करीब एक साल बाद शिंगावा ट्रेन स्टेशन लौटे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से घर से काम कर रहा था और मैं तोक्यों में अपने कार्यालय में आया हूं क्योंकि आज आपातकाल हटा लिया गया। यह एक शुरुआत लग रही है।''

आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर साधा निशाना

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका लंबे समय से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों की पनाहगाहों के संबंध में अपनी चिंताओं को लेकर बहुत ईमानदार रहा है। अफगानिस्तान और अमेरिका ने पहले भी तालिबानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसने देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है, जहां उन्हें पनाह दी जाती है और साथ ही चिकित्सीय इलाज भी दिया जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, ''हम लंबे समय से पनाहगाहों के संबंध में पाकिस्तान के साथ अपनी चिंताओं को लेकर बहुत ईमानदार रहे हैं। ये पनाहगाह सीमा पर उनकी तरफ हैं और ये चिंताएं आज भी बनी हुई हैं।''

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान के पास निश्चित रूप से दुनिया के उस हिस्से में आतंकवाद के संबंध में कुछ समानताएं और जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ''हम अपनी चिंताओं को लेकर पाकिस्तानी नेताओं के साथ स्पष्ट बातचीत करते रहेंगे।'' किर्बी ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी लोग भी उन समूहों और उसी सीमा से पैदा होने वाले आतंकवादी खतरों के पीड़ित रहे हैं।'' काबुल दावा करता है कि इस्लामाबाद युद्ध ग्रस्त देश में लड़ने के लिए हजारों आतंकवादियों को भेज रहा है और तालिबान को पनाह दे रहा है। वहीं, पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान विरोधी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तथा एक अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पनाह देता है। किर्बी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के भीतर ड्रोन हमले जारी रखना अमेरिका के अधिकारों के दायरे में आता है। उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि हमारे पास देश की रक्षा करने का अधिकार है।'' दरअसल, तालिबान ने अमेरिका पर अफगानिस्तान में ड्रोन उड़ाना जारी रखकर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

सीरिया में ढेर हुआ अलकायदा का खूंखार आतंकी सलीम अबू अहमद

वॉशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका ने अलकायदा के खूंखार कमांडर सलीम अबू अहमद को नेस्तानाबूत कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जानकारी दी कि अलकायदा कमांडर सलीम अबू अहमद को सीरिया में एक ड्रोन हमले में मार गिराया गया है। हालांकि इस हमले में किसी भी नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है।

योजनाएं बनाता था अबू अहमद

विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 20 सितंबर को सीरिया के इदलिब शहर पर ड्रोन हमला किया था। जिसमें खूंखार कमांडर अबू अहमद ढेर हो गया। आपको बता दें कि अबू अहमद अलकायदा के लिए पैसे जुटाने का काम किया करता था। इसके अलावा वो अलकायदा के लिए योजनाएं भी तैयार करता था।

जारी रहेंगे अमेरिकी ऑपरेशन्स

प्राप्त जानकारी के मुताबिक अमेरिका अंतरराष्ट्रीय आतकवाद के खिलाफ अपने ऑपरेशन्स को जारी रखेगा। ऐसे में अमेरिका आतंकवादी संगठनों को कमजोर करने के लिए उनके सरगनाओं को निशाना बनाता रहेगा।

चीन ने शिनजियांग के लिए नए गर्वनर की नियुक्ति की, मानवाधिकार हनन के हैं आरोप

बीजिंग। (एजेंसी)।

चीन ने शिनजियांग के लिए नए गवर्नर की नियुक्ति की है, जहां सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पर उईगुरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को हिरासत में लेने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं। पूर्व उप गर्वनर एरकिन तुनियाज ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चीनी नीतियों का जोरदार तरीके से बचाव किया लेकिन सुविधा केंद्रों के संचालन के लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। चीन का कहना है कि इन केंद्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन होता है और लोगों को कट्टरवाद के रास्ते से हटने के लिए प्रेरित किया जाता है।

आलोचक सुविधा केंद्रों को हिरासत केंद्र कहते हैं। उईगुर समुदाय के तुनियाज (59) ने अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की है और वह शिनजियांग में कई पदों पर काम कर चुके हैं। बृहस्पतिवार देर रात तुनियाज की नियुक्ति की घोषणा की गई। क्षेत्र के प्रभावशाली अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन क्वांगुओ हैं जिनकी निगरानी में हिरासत केंद्र बनाए गए और अल्पसंख्यकों की निगरानी की व्यवस्था तैयार की गई।

संयुक्त राष्ट्र में फरवरी में डिजिटल तरीके से संबोधन में तुनियाज ने कहा था, ''इन केंद्रों के सभी प्रशिक्षुओं ने अक्टूबर 2019 में स्नातक किया था, हैं और अब टिकाऊ नौकरी कर रहे हैं और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं।'' पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन केंद्रों को अब स्थायी केंद्रों की तरह बदल दिया गया है जबकि यहां रह चुके लोगों का कहना है कि उन्हें गंभीर हालात का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने पारंपरिक संस्कृति और धर्म का पालन करने की आजादी भी नहीं प्रदान की गई।

देश के सबसे प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानून पर फैसला करेगी टेक्सास की अदालत

ऑस्टिन (अमेरिका)। (एजेंसी)।

एक संघीय न्यायाधीश शुक्रवार को इस बात पर विचार करेगा कि क्या टेक्सास, अमेरिका में सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानून को यथास्थिति में बनाए रख सकता है और महिलाओं को देखभाल पाने के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य की सीमाओं के पार जाना होगा। इस कानून के चलते सितंबर के बाद से अधिकतर गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बाइडन प्रशासन द्वारा दायर एक मुकदमा टेक्सास कानून को पहला कानूनी झटका देना चाहता है जिसे सीनेट बिल 8 के रूप में जाना जाता है, जो अब तक मिली चुनौतियों की एक शुरुआती लहर का सामना कर चुका है - जिसमें अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा इसे लागू रहने की इजाजत देना भी शामिल है। टेक्सास गर्भपात प्रदाता डॉ. गज़ाला मोएदी ने बृहस्पतिवार को गर्भपात की सुविधा पर सुनवाई के दौरान अमेरिकी सदन की निगरानी एवं सुधार समिति को बताया हमारे राज्य में गर्भपात देखभाल लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है।'

टेक्सास का यह कानून भ्रूण में धड़कन सुनाई देने लगने के बाद गर्भपात पर रोक लगाता है, आमतौर पर लगभग छह सप्ताह में भ्रूण में धड़कन सुनाई देती है जब कुछ महिलाओं को पता भी नहीं होता है कि वे गर्भवती हैं। ऑस्टिन के अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉबर्ट पिटमैन शुक्रवार को उन तर्कों को सुनेंगे कि क्या टेक्सास कानून को अस्थायी रूप से रोक सकता है, जो कि पिछले 50 वर्षों में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार के लिए देश का सबसे बड़ा अंकुश है। न्याय मंत्रालय ने अदालत पर तेजी से कार्रवाई करने पर जोर दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पिटमैन कितनी जल्दी फैसला करेंगे।

मदद करने गए डब्ल्यूएचओ के 21 कर्मचारियों ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ किया यौन शोषण

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

कांगो में विश्व स्वास्थ्य संगठन के इक्कीस कार्यकर्ताओं पर इबोला के प्रकोप के दौरान लोगों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है, डब्ल्यूएचओ-कमीशन जांच पैनल ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि 2018-2020 मिशन से जुड़े 83 कथित ऐसे लोगों की पहचान की गई और इनमें से 21 लोग के विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी थे। एसोसिएटेड प्रेस की जांच के महीनों बाद पैनल ने अपने निष्कर्ष जारी किए, जिसमें पाया गया कि डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ प्रबंधन को 2019 में कई दुरुपयोग के दावों के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उत्पीड़न को रोकने में विफल रहा और यहां तक कि इसमें शामिल प्रबंधकों में से एक को पदोन्नत किया गया।

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने घटना पर जताया दुख

स्वतंत्र कमेटी की जांच में खौफनाक हकीकत सामने आने के बाद ह्यूाह प्रमुख टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस ने घटना पर दुख जताया है। टेड्रोस ने कहा कि यह उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है कि गुनाह करने वालों को सजा मिले। गौरतलब है कि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने दावों की जांच के लिए पिछले अक्टूबर में समिति का गठन किया। मीडिया की खबरों में बताया गया था कि कांगो में 2018 में इबोला फैलने के बाद इस संकट से निपटने में लगे अज्ञात अधिकारियों ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद समिति का गठन किया गया। उस वक्त टेड्रोस ने कहा था कि वह ''क्षुब्ध'' हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी कर्मचारी यौन उत्पीड़न में संलिप्त पाया जाएगा उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा।

डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. माइकल याओ को कई बार लिखित में यौन उत्पीड़न के आरोपों की सूचना दी गई। याओ को बाद में पदोन्नति दे दी गई। डब्ल्यूएचओ के चिकित्सक ज्यां पॉल नगान्दु और एजेंसी के दो अन्य अधिकारियों ने एक युवती के लिए जमीन खरीदने का लिखित वादा किया था,जिसे कथित तौर पर गर्भवती बना दिया था। नगान्दु ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करने को कहा गया था। कुछ महिलाओं ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कड़ा दंड मिलेगा।

संपादकीय

कब तक जाम

जब दिल्ली और आसपास के राज्यों में एकाधिक राजमार्गों पर लंबे समय से जाम लगा हो, तब इस परेशानी का फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना स्वागतयोग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वाजिब सवाल उठाया है कि राजमार्गों को इतने लंबे समय के लिए कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? पिछले साल पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम को हमारे शासन-प्रशासन के एक तबके ने मानो भुला ही दिया है। ऐसा लगता है, लोगों को आए दिन होने वाली परेशानी की परवाह न तो किसानों को है और न सरकारों को। जहां भी जाम की स्थिति है, वहां जितनी संख्या में किसानों का डेरा है, उतनी ही संख्या में पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के जवान में भी जमे हुए हैं। ऐसा लगता है, मानो किसान और जवान राजमार्गों पर ही बस गए हों। शीर्ष अदालत नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने नाकाबंदी को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि पहले दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट लगते थे और अब दो घंटे से अधिक का समय लग रहा है और क्षेत्र के लोगों को विरोध-प्रदर्शन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस याचिका पर केंद्र सरकार से यह कहा गया है कि वह किसान संघों को पक्ष बनाने के लिए एक औपचारिक आवेदन दायर करे। लंबे समय से राजमार्गों पर बैठे किसानों का मत जानना जरूरी है, ताकि जाम खुलवाने की दिशा में सुनवाई हो सके। बहुत से लोगों का मानना है कि किसानों के प्रति सरकार का लचीला रुख ही जाम की वजह है, तो कई लोग यह भी मानते हैं कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने किसानों को राजधानी में अंदर आकर बैठने से रोकने के लिए उन्हें सीमा पर ही रोकने की कोशिश की है और सरकार की सहमति से ही कुछ जगहों पर किसानों को जाम लगाने दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर, इससे आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसके प्रति अब सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता वाजिब मुकाम पर पहुंच सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने विश्वास जताया है कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है, पर राजमार्गों को ऐसे कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से पूछा है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है? जवाब मिला कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बैठक की थी और हलफनामे में इसका ब्योरा दिया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार से जो कहा, वह बहुत मायने रखता है। अदालत ने कहा, कानून को कैसे लागू किया जाए, यह आपका काम है। अदालत इसे लागू नहीं कर सकती। इसे लागू करना कार्यपालिका का काम है। बहरहाल अदालत के रुख से ऐसा भी लगा कि वह हस्तक्षेप से बचना चाहती है, क्योंकि एकाधिक मौकों पर जब अदालतों ने समाधान के लिए हस्तक्षेप किया है, तब सरकार की ओर से अधिकारों के अतिक्रमण की बात उठी। जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह और चिंता को सरकार गंभीरता से ले, ताकि पिछले साल 27 नवंबर से ही अवरुद्ध राजमार्ग खुल सकें।

'आज के ट्वीट

बाध्य

कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करें अन्यथा कर्मचारी अगले चरण के आंदोलन के लिए बाध्य होंगे॥।

- बिहार राज्य विवि व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ॥

देश के किसान देश का आधार किन्तु देश के किसान उपेक्षा के शिकार

हमारे देश में जाति, धर्म, विकास, बेरोजगारी ,गरीबी, आरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, जीएसटी, राम मंदिर , जम्मू कश्मीर विवाद ,आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन से परेशानी आदि हर तरह की समस्याओं पर वाद विवाद होते हैं। हर हमेशा कोई न कोई ज्वलंत मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। जिस मुद्दे को जितना राजनीतिक रंग मिलता है वो मुद्दा उतना ही ज्यादा लोकप्रिय होता जाता है।

राजनीतिक पार्टियो द्वारा भी तरह तरह के मुद्दे को मोहरा बनाकर हम आम जनता को ही बेवकूफ बनाया जाता है।चुनावी पार्टियों द्वारा भी चुनाव के वक्त तरह-तरह के एजेंडा जनता के सामने पेश कर रिझाया जाता है।इन एजेंडों में,बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति ,जनजाति ,सभी होते है।देश में सभी तरह के समस्याओं के समाधान का समावेश इस एजेंडों में होता है । किन्तु इस एजेंडों में कृषि एवं किसान सबसे लास्ट नंबर पर आते हैं। क्यो??

आजादी से पहले भी किसानों का अंग्रेजो द्वारा सबसे ज्यादा शोषण हुआ ,आजादी के बाद भी किसानो का शोषण जारी है।

हमारे देश में अगर कोई सबसे ज्यादा कोई उपेक्षित वर्ग है तो वह है, किसान वर्ग ।आए दिन किसानों के द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं । भूखमरी की खबरे आती रहती है ,पर ये खबरे ,हमेशा से उपेक्षित रहा है ,मिडिया के द्वारा भी ,सरकार के द्वारा भी एवं शहरो में रहनेवाली आम जनता के द्वारा भी। किसान की बात आते ही सभी चुप्पी साध लेते है।

पूरे देश के गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मतदाता दिवस आदि बहुत सारे दिवस मनाये जाते है ,मगर किसान को सम्मान देने के लिए हमारे देश में कोई समारोह नही होता क्यों??

हमारा देश सदियों से कृषि प्रधान देश है ।हमारे देश की आर्थिक स्थिति का आधार भी कृषि ही है ।हमारे देश में कुल आबादी का 52ब्र हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ है एवं ,कृषि जनित व्यवसाय में लगा हुआ है। हमारे देश में गेहूं और चावल का उत्पादन चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर होता है ।भारत विश्व में उर्वरक उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है ।आम केला चीकू खट्टा नींबू काजू नारियल मिर्च हल्दी आदि के उत्पादन में भारत विश्व का पहला उत्पादक देश है ।फल और सब्जियां के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर है। कृषि के द्वारा कोई भी व्यवसायिक या खाद्यान्न जनित फसल के मामले में भारत पहले दूसरे या तीसरे स्थान पर है।

भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि होता है। 4% भूमि चारागाह है एवं 21% फीसदी भूमि पर वन है एवं 24% भूमि बंजर है।

कृषि के मामले में भारत पूरे विश्व में लगभग मजबूत स्थिति में है ।हरित क्रांति के बाद इस स्थिति में और मजबूती आई है । लेकिन जितनी ज्यादा मजबूती खाद्यान्न उत्पादन में है,उतनी ही ज्यादा कमजोरी किसानों की जिंदगी में है ।

सदियों पहले जैसे किसान कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर थे आज भी किसानों की वही स्थिति है ।वैसे किसानों के पक्के मकान बन पाए हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख ,कृषि को छोड़कर नौकरी या व्यवसाय में आ गए हैं ।

किसानों की दशा अब भी दयनीय बनी हुई है परंतु ना देश की सरकार और ना ही देश की जनता को इससे कोई फर्क पड़ता है। हमारे देश के लोगों के पास मनोरंजन करने के लिए पैसे हैं। नशाखोरी करने के लिए पैसे हैं। भौतिकवादी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए पैसे हैं । टूर पर जाने के लिए पैसे है ।

मगर ,जैसे ही खाद्यान्न से संबंधित किसी वस्तु का मुल्य बढ़ता है वैसे ही ,आम जनता महंगाई महंगाई हल्ला करना शुरू कर देती है। दाल के दाम बढ़े या सब्जी के दाम बढ़े तो, जनता धरती आसमान एक कर देती है। परंतु ,इन सब मामले में किसी एक जनता का भी ध्यान किसान की ओर नहीं जाता कि, बढ़ती महंगाई के साथ अगर खाद्यान्न की वस्तुओं के भी दाम का तालमेल महंगाई के साथ नहीं किया गया तो किसान की उन्नति कैसे होगी ??

किसान अपनी दयनीय स्थिति में ही जिंदगी जीते रहेगे??

हमारे देश में किसानों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण भारत की अनाज मंडियां है ।भारत में किसानों के खुन पसीने से उगाये गए अनाज का खरीद फरोख्त का जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं ।

हमारे देश में किसानों की दुर्दशा का कारण किसान और अनाज मंडी के बिचौलिए हैं ।यह बिचौलिए बिना कुछ किए लाखों लाख कमा रहे हैं । किसानों से ज्यादा बिचौलिए कमा रहे है। बिना मेहनत के खरीद-फरोख्त के माध्यम से किसानों को ठग रहे हैं ,और अपना पॉकेट भर रहे हैं। सरकार के द्वारा बनाया गया कृषि कानून इन बिचौलियों के कारण दम तोड़ देता है । ऊपर से कालाजारी का हिसाब किताब तो और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ा कर रहा है।

किसानों को अनाज मंडी के भ्रष्टाचार के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है ।किसान से बिचौलिए किसी भी वस्तु को रू100 में खरीदते हैं और उसे 180 या रू200 में खुदरा मार्केट में बेचते हैं । यही हिसाब किताब सब्जी से लेकर अनाज दलहन तिलहन सबका यही हाल है।

कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां उत्पादनकर्ता को सबसे कम पैसे मिलते हैं एवं एजेंट को बिचौलियों को ज्यादा पैसे मिलते है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि , किसानों के लिए एक सुरक्षित और मुनाफा देनेवाला कानून लागू किया जाए ।ताकि अनाज मंडी और किसानों के बीच पारदर्शिता बनी रहे । किसानों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके,तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा ।

किसानों की ढुलमुल स्थिति के कारण ही हमारे देश का विकास भी ढुलमुल है । जब तक सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता की व्यवस्था नहीं होगी कालाबाजारी को नहीं रोका जाएगा। बिचौलियों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तब तक किसानों की दशा में सुधार नहीं हो पाएगा।

लेखिका: सुनीता कुमारी
पूर्णियाँ ,बिहार

प्रकृति का दीदार

जग्गी वासुदेव

आमतौर पर माना जाता है कि दुनिया में फिलहाल सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली फिनलैंड की है। फिनलैंड ने आज से चालीस साल पहले अपनी शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करना शुरू किया था। लगभग उसी समय अमेरिका ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली पर काम करना शुरू किया था। इस कोशिश में अमेरिका मानकीकरण (स्टैंडर्ड तय करना) व टेस्टिंग (परीक्षाओं) के रास्ते पर चला गया, उसने अपना पाठ्यक्रम भी कम किया, लेकिन ये सब कारगर साबित नहीं हुआ। शिक्षा पर खरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन ऐसा कोई सुधार सामने नहीं आया, जिसके बारे में बात की जाए।इतना ही नहीं, टीचर्स व प्रिंसिपल्स में जबरदस्त निराशा घर कर गई, दूसरी तरफ बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि भर गई। इस बीच फिनलैंड पिछले चालीस सालों में दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था बन गया, जहां विद्यार्थियों की उपलब्धियां हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ते, उनको पढ़ाई से संतुष्टि मिलती है। टीचर्स के लिए भी एक सम्मान है, अभिभावक (माता-पिता) भी संतुष्ट हैं। और इन सबसे उनके समुदायों में एक स्थायित्व है।इन वजहों से वहां की शिक्षा व्यवस्था एक उदाहरण बन गई है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सूचकांक हैं, वे दिखाते हैं कि फिनलैंड टेस्टिंग के मामले में सबसे ऊंचे स्थान पर है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था कम्पीटीशन पर नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन यानी सहयोग पर आधारित है। वहां स्कूल आपस में मिलकर काम करते हैं, टीचर्स मिलकर काम करते हैं, यूनिवर्सटिी स्कूल के साथ, अभिभावकों (माता-पिता) के साथ मिलकर काम करती हैं। वहां बस हाईस्कूल की आखिरी परीक्षा को छोड़कर कोई मानक परीक्षा नहीं होती। इतना ही नहीं, वहां ग्रेजुएशन की दर लगभग सौ फीसद है। तो ऐसा नहीं है कि हमें फिनलैंड की सारी चीजें यहां लागू कर देनी चाहिए। असली चीज है कि सिद्धांतों का इस्तेमाल होना चाहिए और ये सिद्धांत बेहद बेबाक और स्पष्ट हैं। आधुनिक शिक्षा की शुरु आत औद्योगिक क्रांति से हुई है और आप इसे देख सकते हैं। ये औद्योगिक क्रांति सफल तो बहुत हुई है, लेकिन ये मशीनी और अप्राकृतिक है। केन ने जो कहा, वह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि यह एक प्रोडक्शन लाइन नहीं है। यह एक जैविक (आर्गेनिक) घटना है।

आज का राशिफल

मेष प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी या खोने की आशंका है।

वृषभ व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। राजनैतिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। प्रणय संबंध मधुर होंगे। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी।

मिथुन जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। किसी अभिन्न मित्र से मिलाप की संभावना है। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। खान-पान में संयम रखें। संतान के संबंध में चिंतित रहेंगे।

कर्क प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुटुम्बजनों का सहयोग मिलेगा। धन हानि के योग हैं।

सिंह जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

कन्या आर्थिक योजना फलीभूत होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाणी की सौम्यता बनाये रखें। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

तुला पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।

वृश्चिक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। वाणी की सौम्यता से व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। नए अनुबंध प्राप्त होंगे।

धनु व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है।

मकर शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। मनोरंजन के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के योग हैं।

कुम्भ पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किसी का वाणी के स्तर पर उत्पीड़न न करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

मीन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। धन, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

चुनौतियों में चन्नी चुनें उम्मीदों की राह

अश्विनी कुमार

चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में बनी कांग्रेस सरकार पंजाब के समकालीन राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। यह द्योतक है एक नये उभरते शक्ति ढांचे और बढ़ती सामाजिक शक्तियों का स्वागत करती मान्यताओं का। फिलवक्त, नयी राज्य सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। पार्टी हाईकमान ने मशक्कत से सूबा इकाई में एकता की खातिर जिस नाजुक समझौतापरक व्यवस्था का इंतजाम किया है, उसमें निहित जन्मजात दबावों और खिंचावों के बीच जुगत से राह पकड़नी होगी। जिन हालातों में चन्नी को सबसे ऊंचा ओहदा मिला है, राज्य के हितों के लिए उन्हें बहुत सूझबूझ का परिचय देना होगा। साथ ही अप्रत्याशित मिज़ाज वाले साथियों को मान-मनौव्वल-खुशामद से साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। जो ऐतिहासिक मौका उन्हें मिला है, उसमें मुख्यमंत्री काल के लिए बहुत कम मिले समय की परवाह न करते हुए, सूबे के भविष्य की खातिर दूरदृष्टि अपनाकर मूल समस्याएं जैसे कि गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर फसल चक्र विविधता अपनाना और किसानों की आय सुरक्षा को यकीनी बनाना जैसी तात्कालिक जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए।उन्हें एक पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना होगा और राज्य में रोजागार एवं कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र द्वारा बड़े निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें महिला सशक्तीकरण पर खास ध्यान हो। सूबे के स्वास्थ्य ढांचे में बड़े स्तर पर विस्तार करने को और ज्यादा टालना उचित नहीं होगा, न ही राज्य सरकार को कोविड प्रबंधन में अपनी सावधानियां कम करनी चाहिए। एक फौरी उपाय के तौर पर राज्य सरकार वैध उपायों से बिजली दर में कमी सुनिश्चित करे, चाहे तो बिजली बिलों की अस्थाई माफी भी की जा सकती है। राजनीतिक स्तर पर, मुख्यमंत्री सूबा पार्टी प्रधान के साथ मिलकर किसान संगठनों से संपर्क बनाए रखें ताकि उनकी मांगों के साथ एकजुटता और सतत समर्थन का भाव बना रहे। सबसे बड़ी चुनौती जो चन्नी सरकार के सामने है, वह है राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना। धार्मिक ग्रंथों की हुई बेअदबी के मामले के दोषियों और नशा व्यापार के बड़े सरगनाओं को सजा दिलाने की लगातार चली आ रही मांग को पिछले अदालती फैसलों और आदेशों की बाध्यता के आलोक में कानूनी विकल्पों के दायरे के अंतर्गत पूरा करने पर ध्यान दिया जाए। यह अतिसंवेदनशील मुद्दा, जो संवैधानिक-प्रशासनिक कौशल का इम्तिहान भी है, उसको हल करना मुख्यमंत्री की बुद्धिमत्ता का परिचायक होगा। चुनाव करने जो विकल्प उनके सामने है, वह वास्तव में बहुत कठिन हैं। पदग्रहण करते वक्त संविधान बनाए रखने वाली शपथ के साथ लोगों की संवेदनशीलता का भान अवश्य रखना होगा। ऐसा न लगे कि उनका राज राजनीतिक प्रतिशोधी या बढ़ा चढ़ा कर किए अपने दावों का बंधक हो गया है। एक संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने को एक बुद्धिपरक सबक यह है कि जो कानून के दायरे में रहते हैं, वे अपनी निजी इच्छा से इतर इसमें निहित आदेशों से बंधे होते हैं। साफ है, कानून के अनुशासन से बंधी एक सरकार को अपने राजनीतिक विरोधियों को निजी दुश्मन की तरह लेकर, जोर जबरदस्ती वाली राजकीय शक्तियों का दुरुपयोग करके 'राह पर लाने' या जब इच्छानुसार 'राह से हटवा देने' वाली प्रवृत्ति पालने से गुरेज करना चाहिए। अंतिम आकलन यह कि दोस्त हो या दुश्मन, सबके लिए कानून एक जैसा केवल कहने भर का जुमला न होकर इस पर मूर्त रूप से अमल होता दिखाई दे। यह करना ही राजधर्म का निर्वहन है, जिसकी पालना करवाना नयी सरकार के प्रशासन की कानूनन वैधता सुनिश्चित करवाएगी। राजकीय शक्ति का इस्तेमाल सूबे में शांति बनाने में किया जाए ताकि सरकार को अन्य जरूरी विषय निपटाने का समय मिले। ऐसे में जब राज्य में चुनाव होने में 100 दिन से कम समय है, मुख्यमंत्री और उनके साथियों को प्रशासनिक कार्यों की एवज पर अपना ध्यान विपक्षियों के आंदोलनों से भटकने नहीं देना होगा। हो सकता है इसमें धार्मिक संवेदशीलता और जातिवाद वाला पुट भी हो और परिणामस्वरूप भयानक सांप्रदायिक और सामाजिक रार पैदा करने वाला हो। विगत में देश की एकता और अखंडता कायम रखने की खातिर पंजाब ने आतंकवाद और चरमपंथ की काफी मार सही थी। अब एक और संघर्ष-टकराव और इसमें निहित दर्दनाक संताप सहना गवारा नहीं कर सकता। वास्तव में, शांति-सामाजिक एकजुटता-सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना राज्य का सर्वप्रथम फर्ज और राजनीतिक प्रबंधन कौशल होता है। एक अन्य मूल स्तर पर, नयी सरकार, जिसने प्रजातंत्र और सबको साथ लेकर चलने की शपथ ली है, उसे याद रखना होगा कि सही मायनो में एक जीवंत लोकतंत्र केवल वह नहीं है, जिसमें समय-समय पर चुनाव हों, बल्कि वह है जहां बिना किसी डर के प्रतिवाद व्यक्त करने की आजादी हो। यह एक 'धूर्त का दंभी शासन' न होकर जनसाधारण की गरिमा और हाशिये पर आने वालों के लिए भी दयाभाव रखने वाले आदर्शों से परिपूर्ण हो। हमें यह नहीं भूलना है कि एक प्रजातांत्रिक प्रशासन के कामकाज पर जनता द्वारा नैतिकता पर न्यायोचित सवाल उठाने का हक एक जरूरी अवयव होता है। कठिन राह पर बढ़ते करते वक्त मुख्यमंत्री चन्नी से उम्मीद है कि वह ऐसी राह पर बढ़ेंगे, जिससे सभी पंजाबियों को हौसला हो कि वक्त के साथ बेहतर जिंदगी और ऐसा भविष्य बनेगा, जिसको मूर्त रूप में पाने की वे कामना रखते हैं। आखिर में, राजनीति के मोड़ों और बदलते हालातों के बीच, चन्नी को वक्ती मित्रों की अस्थाई वफादारी और विरोधियों की स्थाई दुश्मनी से सावधान रहना होगा और इनका वजूद रोजाना की राजनीति का अंग है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, मेरी बधाई और शुभकामनाओं सहित, आप आगे बढ़ें।

लेखक पूर्व केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं। व्यक्त विचार निजी हैं।

महात्मा गांधी
स्वतंत्र भारत के पिता

भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास कर्मचंद गांधी जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, के जन्म दिन 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वस्तुतः गांधीजी विश्व भर में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, और यह दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है ।

मोहनदास करमचंद गांधी (2 अक्तूबर 1869 - 30 जनवरी 1948) भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह - व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे, उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा पर रखी गई थी जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत- महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द जिसे सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टेगौर ने प्रयोग किया और भारत में उन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। उन्हें सरकारी तौर पर राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया है 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिन राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है और दुनियाभर में इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी ने रोजगार अहिंसक सविनय अवज्ञा प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका, में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया। 1915 में उनकी वापसी के बाद उन्होंने भारत में किसानों , कृषि मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्याधिक भूमि कर और भेदभाव के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद गांधी जी ने देशभर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण, आत्म-निर्भरता के लिए अस्पृश्यता का अंत आदि के लिए बहुत से आंदोलन चलाएं। किंतु इन सबसे अधिक विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाले स्वराज की प्राप्ति उनका प्रमुख लक्ष्य था। गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में दांडी मार्च और इसके बाद 1942 में , ब्रिटिश भारत छोड़ो आन्दोलन छेडकर भारतीयों का नेतृत्व कर प्रसिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने आत्म-निर्भरता वाले आवासीय समुदाय में अपना जीवन गुजारा किया और पंरपरागत भारतीय पोशाक धोती और सूत से बनी शॉल पहनी जिसे उसने स्वयं ने चरखे पर सूत कात कर हाथ से बनाया था। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि तथा सामाजिक प्रतिकार दोनों के लिए लंबे-लंबे उपवास भी किए।

गांधी दक्षिण अफ्रीका में (1895)

दक्षिण अफ्रीका में गान्धी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरम्भ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इन्कार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अन्दर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएँ गान्धी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरुकता का कारण बनीं तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुईं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गान्धी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाये।

1906 के जुलु युद्ध में भूमिका

1906 में, दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव कर के लागू करने के बाद दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जूलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। उनका तर्क था अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। तथापि, अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इंकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्टेचर पर लाने के लिए स्वैच्छा पूर्वक कार्य कर सकते हैं। इस कोर की बागडोर गांधी ने थामी। 21 जुलाई 1906 को गांधी जी ने इंडियन ओपिनिय में लिखा कि 23 भारतीय निवासियों के विरूद्ध चलाए गए आप्रेशन के संबंध में प्रयोग द्वारा नेटाल सरकार के कहने पर एक कोर का गठन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों से इंडियन ओपिनियन में अपने कॉलमों के माध्यम से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया और कहा, यदि सरकार केवल यही महसूस करती है कि आरक्षित बल बेकार हो रहे हैं तब वे इसका उपयोग करेंगे और असली लड़ाई के लिए भारतीयों का प्रशिक्षण देकर इसका अवसर देंगे।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष

1915 में, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आएं।उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन वे भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले जो एक सम्मानित नेता थे पर ही आधारित थे।

चंपारण और खेड़ा - गांधी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चम्पारन और खेड़ा सत्याग्रह, आंदोलन में मिली हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाए नकद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। जमींदारों (अधिकांश अंग्रेज) की ताकत से दमन हुए भारतीयों को नाममात्र भरपाई भत्ता दिया गया जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गांवों को बुरी तरह गंदा और अस्वास्थ्यकर और शराब, अस्पृश्यता और पर्दा से बांध दिया गया। अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिए जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढता ही गया। यह स्थिति निराशजनक थी। खेड़ा, गुजरात में भी यही समस्या थी। गांधी जी ने वहां एक आश्रम बनाया जहाँ उनके बहुत सारे समर्थकों और नए स्वेच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया। उन्होंने गांवों का एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखाजोखा रखा गया और इसमें लोगों की अनुत्पादकीय सामान्य अवस्था को भी शामिल किया गया था। ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गांवों की सफाई करने से आरंभ किया जिसके अंतर्गत स्कूल और अस्पताल बनाए गए और उपरोक्त वर्णित बहुत सी सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रेरित किया।

असहयोग आन्दोलन - गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ़ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फोजों द्वारा भारतीयों पर जलियावांला नरसंहार जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है ने देश को भारी आघात पहुंचाया जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधीजी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भर्त्सना की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। किंतु ऐसा इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार आर भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था जो जल्दी ही स्वराज अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं राजनैतिक आजादी में बदलने वाला था।

स्वराज और नमक सत्याग्रह - गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता , शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे। उन्होंने पहले 1928 में लौटे एक साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवेधानिक सुधार आयोग बनाया जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका परिणाम भारतीय राजनैतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला। दिसंबर 1928 में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था अथवा ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। गांधी जी ने न केवल युवा वर्ग सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरूषों द्वारा तत्काल आजादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया बल्कि अपनी स्वयं की मांग को दो साल की बजाए एक साल के लिए रोक दिया। अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं 31 दिसंबर 1929 , भारत का झंडा फहराया गया था लाहौर में है . 26 जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया। इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया जिसे 12 मार्च से 6 अप्रेल तक नमक आंदोलन के याद में 400 किलोमीटर (248 मील) तक का सफर अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से अधिक लोगों को जेल भेजा।

द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो - द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जब छिड़ने नाजी जर्मनी आक्रमण पोलैंड. आरंभ में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना इसमें एकतरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद, गांधी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आजादी से इंकार किया गया हो तब लोकतांत्रिक आजादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढता गया गांधी जी ने आजादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेजों को भारत छोड़ो आन्दोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। यह गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था जो भारतीय सीमा से अंग्रेजों को खदेड़ने पर लक्षित था। गांधी जी के दूसरे नंबर पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य राजनैतिक भारतीय दलों ने आलोचना की जो अंग्रेजों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही विश्वास रखते थे। कुछ का मानना था कि अपने जीवन काल में अथवा मौत के संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करना एक नश्वर कार्य है जबकि कुछ मानते थे कि गांधी जी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारत छोड़ो इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख?या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे तब तक भारत को तत?काल आजादी न दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी यह आन्दोलन बन्द नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को मूर्त रूप दिया जाता है। उन्होने कहा कि उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो (अंग्रेजी में डू ऑर डाय) के द्वारा अन्तिम स्वतन्त्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा।

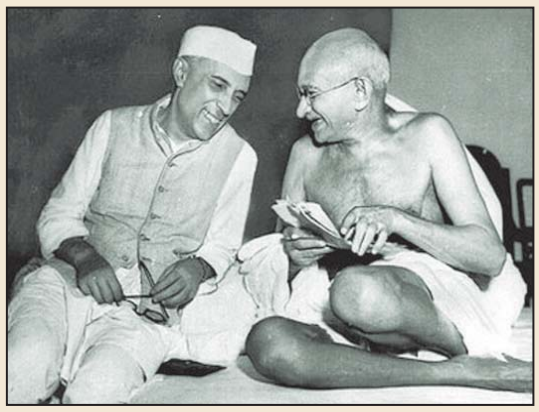

स्वतंत्रता और भारत का विभाजन

गांधी जी ने 1946 में कांग्रेस को ब्रिटिश केबीनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योंकि उसे मुस्लिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित समूहीकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी। चूंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। 1948 के बीच लगभग 5000 से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे।भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिक्खों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मुहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता ने, पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और ईस्ट बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदु मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांगेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बझना बसंभव था चुकि पाटर्ठी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी। गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मज़बूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी।

हत्या

30 जनवरी 1948 गांधी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिड़ला भवन के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गौड़से हिन्दू राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदु महासभा के साथ संबंध थे जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोड़से और उसके उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 15 नवंबर1949 को इन्हें फांसी दे दी गई।

गांधी जयंती
आत्ममूल्यांकन का दिन

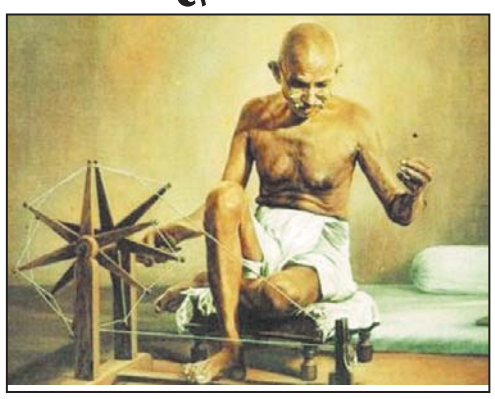

आज गांधी जयंती है। गांधी प्रतिमाओं और उनकी तस्वीरों को पिछली पुण्यतिथि के बाद धोने-पोंछने का यह पहला अवसर आया है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है, जयंती और पुण्यतिथि के बीच की अवधि में गांधीजी के साथ कोई नहीं होता है। कड़वी बात तो यह है कि बचे-खुचे गांधीवादी भी नहीं। वे गांधीजी का साथ दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि जरूरतों और परिस्थितियों ने उन्हें भी सिखा दिया है कि गांधी बनने से केवल प्रताड़ना मिल सकती है, संपदा, संपत्ति नहीं। वैचारिक धरातल में यह खोखलापन एक दिन या एक माह या एक वर्ष में नहीं आ गया। जान-बूझकर धीरे-धीरे और योजनाबद्ध ढंग से गांधी सिद्धांतों को मिटाया जा रहा है क्योंकि यह मौजूदा स्वार्थों में सबसे बड़े बाधक हैं। गांधी सिद्धांतों को मिटाने की इस गतिविधि को देखा नहीं गया, ऐसा नहीं है। सब चुप हैं क्योंकि अपना-अपना लाभ सभी को चुप रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। आमतौर पर जन्मदिन या जयंती के दिन आस्था के फूल अर्पित करने की परंपरा है। इस दिन कड़वी बातों को कहने का रिवाज नहीं है। यदि इस रिवाज को तोड़ा जा रहा है, तो मजबूरी के दबाव को समझे जाने की आवश्यकता है। यह राष्ट्र नेताओं को महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर कीचड़ उछालने की अनुमति कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है? यह कैसी सहिष्णुता है जो राष्ट्र की बुनियादी विचारधारा को मटियामेट करने पर आमादा है?

कहते हैं कि जो राष्ट्र अपने चरित्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। क्या परमाणु बम भारतीयता की रक्षा कर पाएगा? दरअसल, यह भुला दिया गया है कि पहले विश्वास बनता है, फिर श्रद्धा कायम होती है। किसी ने अपनी जय-जयकार करवाने के लिए क्रम उलट दिया और उल्टी परंपरा बन गई। अब विश्वास हो या नहीं हो, श्रद्धा का प्रदर्शन जोर-शोर से किया जाता है। गांधीजी भी श्रद्धा के इसी प्रदर्शन के शिकार हुए हैं। उनके सिद्धांतों में किसी को विश्वास रहा है या नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जयंती और पुण्यतिथि पर उनकी कसमें खाकर वाहवाही जरूर लूटी जा रही है। गांधीजी के विचार बेचने की एक वस्तु बनकर रह गए हैं। वे छपे शब्दों से अधिक कुछ नहीं हैं। इसलिए ही गांधीजी की जरूरत आज पहले से कहीं अधिक है। इस जरूरत को पूरा करने की सामर्थ्य वाला व्यक्तित्व दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हर कोई चाहता है कि आदर्श और मूल्य इतिहास में बने रहें और इतिहास को वह पूजता भी रहेगा। परंतु अपने वर्तमान को वह इस इतिहास से बचाकर रखना चाहता है। अपने लालच की रक्षा में वह गांधी की रोज हत्या कर रहा है, पल-पल उन्हें मार रहा है और राष्ट्र भीड़ की तरह तमाशबीन बनकर चुपचाप उसे देख रहा है। शायद कल उनमें से किसी को यही करना पड़े! अपने हितों की विरोधी चीजों को इतिहास में बदल देने में भारतीयता आजादी के बाद माहिर हो चुकी है। वर्तमान और इतिहास की इस लड़ाई में वर्तमान ही जीतता आ रहा है क्योंकि इतिहास की तरफ से लड़ने वाले शेष नहीं हैं। आज गांधी जयंती है। गांधीजी की प्रतिमा के सामने आंख मूंदकर कुछ क्षण खड़े रहने वाले क्या यह पश्चाताप कर रहे होंगे कि वे गांधीजी के बताए रास्तों पर क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, वे यह कतई नहीं सोच रहे होंगे। तब वे मन ही मन क्या कह रहे होंगे? सोचिए और उस पर मनन कीजिए। गांधी जयंती पर यही बड़ा काम होगा।

गांधीजी ने बजाया था सत्याग्रह का बिगुल

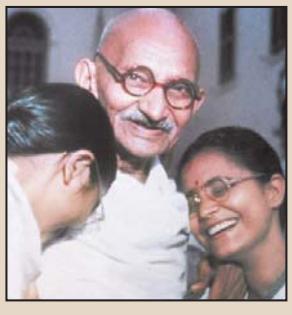

दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारतवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी नेशनल इण्डियन कांग्रेस की स्थापना की। पहली बार सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग किया और विजय भी पाई। इस प्रकार सन? 1914-15 में गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापिस भारत लौटे, तब तक इन विचारों और जीवन-व्यवहारों में आमूल-चूल परिवर्तन आ चुका था।

भारत लौटकर कुछ दिन गांधी जी देश का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेते रहे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था को पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य देकर संघर्ष में कूद पड़े। क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध में वचन देकर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के प्रति अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया था, इससे गांधी जी और भी चिढ़ गए और अंग्रेजी कानूनों का बहिष्कार और सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया। भारतवासियों के मानवाधिकारों का हनन करने वाले रोलट एक्ट का स्थान-स्थान पर विरोध-बहिष्कार होने लगा। सन 1919 में जलियां-वाला बाग में हो रही विरोध-सभा पर हुए अत्याचार ने गांधी जी की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया। सो अब ये समूचे स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर सम्हाल खुलम-खुल्ला संघर्ष में कूद पड़े। इनका संकेत पाते ही सारे देश में विरोधी आंदोलनों की एक आंधी सी छा गई। अंग्रेज सरकार की लाठी-गोलियां भी अंधाधुंध बरसने लगीं। जेलें सत्याग्रहियों से भर उठीं। गांधीजी को भी जेल में डाल दिया गया। बिहार की नील सत्याग्रह, डाण्डी यात्रा या नमक सत्याग्रह, खेड़ा का किसान सत्याग्रह आदि गांधी जी के जीवन के प्रमुख सत्याग्रह हैं। इन्हें कई बार महीने-महीने भर का उपवास भी करना पड़ा। अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए इन्होंने नवजीवन और यंग इण्डिया जैसे पत्र भी प्रकाशित किए। विदेशी-बहिष्कार और विदेशी माल का दाह, मद्य निषेध के लिए धरने का आयोजन, अछूतोद्धार, स्वदेशी प्रचार के लिए चर्खे और खादी को महत्व देना, सर्वधर्म-समन्वय और विशेषकर हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए प्रचार इनके द्वारा आरंभ किए गए अन्य प्रमुख सामाजिक सुधारात्मक कार्य माने गए हैं। इस प्रकार के स्वतंत्रता दिलाने वाले प्रयासों के लिए अक्सर बीच-बीच में इन्हें जेलयात्रा भी करनी पड़तीं। सन 1931 में इग्लैंड में संपन्न गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी वहां गए, पर जब इनकी इच्छा के विरुद्ध हरिजनों को निर्वाचन का विशेषाधिकार हिन्दुओं से अलग करके दे दिया, तो भारत लौटकर गांधी जी ने पुनः आंदोलन आरंभ कर दिया। बंदी बनाए जाने पर जब ये अनशन करने लगे, तो सारा देश क्षुब्ध हो उठा। फलतः ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के मतानुसार हरिजनों का पृथक निर्वाचनाधिकार का हठ छोड़ना पड़ा।

भारत की विनिर्माण गतिविधियों में सितंबर में सुधार: पीएमआई

नई दिल्ली: कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील के बीच मांग की स्थिति में सुधार के चलते भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में सितंबर में सुधार देखने को मिला। एक मासिक सर्वेक्षण में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित आईएचएस मार्किट भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त के 52.3 से बढ़कर सितंबर में 53.7 हो गया, जो व्यापक रूप से व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूत विस्तार का संकेत देता है। पीएमआई आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में लगातार तीसरे महीने समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार का संकेत मिला। पीएमआई की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है। आईएचएस मार्किट की संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा कि मांग में बढ़ोतरी के साथ ही भारतीय विनिर्माताओं ने सितंबर में उत्पादन काफी हद तक बढ़ाया।

सितंबर में हुंदै की बिक्री में 24% की गिरावट

नई दिल्ली: हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने शुक्रवार को बताया कि सितंबर में उसकी कुल बिक्री 23.6 प्रतिशत घटकर 45,791 इकाई रह गई। एचएमआईएल ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में वाहनों के 59,913 इकाइयों की बिक्री की थी। कंपनी ने कहा कि वाहनों की घरेलू बिक्री, सितंबर 2020 में 50,313 इकाइयों के मुकाबले 34.2 प्रतिशत घटकर 33,087 इकाई रह गई। पिछले साल सितंबर में 9,600 इकाइयों के निर्यात की तुलना में इस बार निर्यात 34.3 प्रतिशत बढ़कर 12,704 इकाई हो गया। कंपनी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सेमी-कंडक्टर की आपूर्ति में बाधा ने वाहन विनिर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके चलते सितंबर 2021 में आपूर्ति कम रही।

ओयो आईपीओ से जुटाएगी 8,430 करोड़, सेबी से मांगी मंजूरी

नई दिल्ली । आतिथ्य सत्कार क्षेत्र की कंपनी ओयो ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 8,430 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष दायर मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक आईपीओ में 7,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम होगा, जबकि इसमें 1,430 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश शामिल है। निर्गम से मिली राशि का इस्तेमाल पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा, जिसमें ओयो की सहायक कंपनियों द्वारा लिया गया 2,441 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है। इसके अलावा आईपीओ से जुटाई गई राशि कारोबार विस्तार और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए खर्च की जाएगी।

सेमसंग पर 350 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली ।

नीदरलैंड में बाजार स्पर्धा के नियमों के उलंघन के मामले में सेमसंग इलक्ट्रा निक्स पर करीब 46 मिलियन डॉलर (लगभग 350 करोड़ रुपए) का भारी जुर्माना लगा है। हाल ही में सैमसंग नीदरलैंड में ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ प्राइस फिक्सिंग के मामले में घिर गई है, जिसे नीदरलैंड अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर एंड मार्केट ने बहुत गंभीरता से लिया है। सैमसंग की इस हरकत को वहां के बाजार स्पर्धा नियमों का उलंघन माना गया है, जिसके चलते अथॉरिटी ने 46 मिलियन डॉलर मतलब करीब 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने का ऐलान किया है। नीदरलैंड में ऑनलाइन रिटेलर्स अभी भी साल 2013-2018 वाली तय कीमत पर टीवी बेच रहे हैं। सेमसंग की तरफ से लगातार उन पर कीमत को बढ़ाने का दवाब बनाया जा रहा था, किसी भी ब्रांड द्वारा रिटेल प्राइस तय करना वहां के नियमों के खिलाफ है। जिसके बाद नीदरलैंड की अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर एंड मार्केट (एसीएम) ने ब्रांड पर जुर्माने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि नीदरलैंड में रिटेलर्स अपने हिसाब से टेलिविजन की कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी टेलिविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिटेलर्स पर कीमत तय करने का दबाव नहीं डाल सकती है। बताया जा रहा है कि जांच में सेमसंग की तरफ से रिटेलर्स को किए गए ई-मेल और वाटसएप सबूत के तौर पर मिले हैं। जबकि इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए सेमसंग ने कहा है कि उनकी तरफ से नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और कंपनी एसीएम के फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

एचडीएफसी बैंक के अतिरिक्त मसाला बांड एनएसई आईएफएससी के मंच पर सूचीबद्ध हुए

नई दिल्ली:

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसई आईएफएससी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने ऋण प्रतिभूति बाजार मंच पर एचडीएफसी बैंक के अतिरिक्त मसाला बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। भारतीय इकाई द्वारा विदेशों में रुपए के मूल्य में जारी बांड को मसाला बांड कहते हैं। एनएसई आईएफएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एचडीएफसी बैंक के अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) मसाला बॉन्ड ऋण प्रतिभूति बाजार मंच पर सूचीबद्ध हुए हैं। एनएसई आईएफएससी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''एचडीएफसी बैंक ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर के मध्यम अवधि के पत्र कार्यक्रम के तहत 739 करोड़ रुपए जुटाए हैं।''

सोने और चांदी में आयी तेजी

नई दिल्ली ।

घरेलू बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी में तेजी आई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में 555 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त आई। इसी के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का भाव 45,472 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आई और ये 1,752 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गईं। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में भारी तेजी रही और ये 975 रुपये की बड़ी छलांग के साथ ही 58 हजार रुपये के ऊपर जाकर 58,400 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुईं हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम में अधिक बदलाव नहीं हुआ और ये 22.16 डॉलर प्रति औंस पर ही रहे।

59 हजार अंक की ऊंचाई से भी गिर गया शेयर बाजार

मुंबई:

घरेलू स्तर पर पिछले चार दिनों से लगातार जारी बिकवाली के दबाव में मंगलवार को 60 हजार अंक के रिकॉर्ड स्तर से लुढ़कने के बाद शेयर बाजार आज 59 हजार अंक के शिखर से भी गिर गया। विदेशी बाजारों की गिरावट से निराश निवेशकों की स्थानीय स्तर पर बजाज फिनसर्व, मारुति, एयरटेल, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी समेत 19 कंपनियों में हुई बिकवाली से बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को 360.78 अंक लुढ़ककर 59 हजार अंक से नीचे 58,765.58 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 86.10 अंक उतरकर 17532.05 अंक पर रहा। इस तरह मंगलवार से लेकर आज तक सेंसेक्स 1300 अंक से अधिक टूट चुका है। दिग्गज कंपनियों की तरह जहां मझौली कंपनियें में बिकवाली हुई वहीं छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का भरोसा दिखा। इस दौरान बीएसई का मिडकैप 28.89 अंक फिसलकर 25,224.20 अंक पर रहा जबकि स्मॉलकैप 133.88 अंक की तेजी के साथ 28,215.62 अंक पर पहुंच गया। बीएसई में कुल 3408 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1809 में तेजी और 1420 में मंदी रही जबकि 179 के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई में 24 कंपनियों के शेयर चढ़े जबकि 26 के भाव गिर गए। इस दौरान 11 समूह के शेयर गिरे जबकि आठ में तेजी रही। रियल्टी ने सबसे अधिक 1.56 प्रतिशत का नुकसान उठाया। इसी तरह दूरसंचार 1.31, टेक 0.77, कैपिटल गुड्स 0.21, बैंकिंग 0.52, ऑटो 0.21, आईटी 0.63, इंडस्ट्रियल्स 0.16, वित्त 0.70, सीडीजीएस 0.08 और एफएमसीजी 0.04 प्रतिशत उतर गए। वहीं, शेष आठ समूहों में 0.85 प्रतिशत तक की बढ़त रही। विदेशी बाजारों में गिरावट का रुख रहा। ब्रिटेन का एफटीएसई 0.98, जर्मनी का डैक्स 0.79, जापान का निक्केई 2.31 और हांगकांग का हैंगसैंग 0.36 प्रतिशत टूटा जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.90 प्रतिशत की तेजी रही। कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स 236.59 गिरकर 59 हजार अंक से नीचे 58,889.77 अंक पर खुला और दोपहर से पहले लिवाली के बल पर 58,890.08 अंक उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इसके बाद हुई बिकवाली के दबाव में यह 58,551.14 अंक के निचले स्तर तक फिसल गया। अंत में पिछले दिवस के 59,126.36 अंक की तुलना में 0.61 प्रतिशत कमजोर होकर 58,765.58 पर रहा। निफ्टी भी 86.25 अंक फिसलकर 17,531.90 पर खुला और कारोबार के दौरान 17,557.15 अंक के उच्चतम और 17,452.90 अंक के न्यूनतम स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 17,618.15 अंक के मुकाबले 0.49 प्रतिशत टूटकर 17,532.05 अंक पर रहा। नुकसान उठाने वाली कंपनियों में बजाज फिनसर्व 3.45, मारुति 2.39, एयरटेल 2.22, एशियन पेंट 2.02, बजाज फाइनेंस 1.94, एचडीएफसी 1.54, एनटीपीसी 1.41, आईसीआईसीआई बैंक 1.23 और टीसीएस 1.20 प्रतिशत शामिल रहीं। इनके अलावा अन्य कंपनियां भी 0.82 प्रतिशत तक की गिरावट पर रहीं। वहीं, इस दौरान महज 11 कंपनियों के शेयर चढ़े। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सबसे अधिक 3.05 प्रतिशत का मुनाफा कमाया। इनके अलाव शेष अन्य कंपनियों के शेयरों में 1.24 प्रतिशत तक की तेजी रही।

एयर इंडिया के स्वामित्व पर अगले कुछ दिनों में फैसला : सूत्र

नई दिल्ली।

एयर इंडिया के नए मालिकों के बारे में अगले कुछ दिनों में फैसला किया जाएगा। राष्ट्रीय विमान वाहक की वित्तीय बोलियों की जांच की जा रही है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा, बोली लगाने वालों में से एक टाटा संस को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। इससे पहले टाटा संस ने एसपीवी का समर्थन किया था और उद्योगपति अजय सिंह ने व्यक्तिगत हैसियत से अपनी वित्तीय बोलियां भेजी थीं। तदनुसार, सूत्रों ने कहा कि एयरलाइन के लिए निर्धारित एक रिजर्व प्राइस के खिलाफ दो बोलियों की जांच की जा रही है। यदि बोली रिजर्व प्राइस से कम आती है तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आधिकारिक मोर्चे पर, डीआईपीएएम के सचिव तुहिन कांता पांडे ने शुक्रवार को ट्वीट किया, एआई विनिवेश मामले में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बोलियों को मंजूरी देने का संकेत देने वाली मीडिया रिपोर्ट गलत है। जब इसपर निर्णय लिया जाएगा तो मीडिया को सरकार के निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी दो बोलीदाताओं के साथ बिक्री के अन्य पहलुओं जैसे क्षतिपूर्ति खंड और एयरलाइन के ऋण स्तर को आगे बढ़ाने के बारे में अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं। कमोबेश, अंतिम निर्णय अगले कुछ दिनों के भीतर एआईएसएएम (एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म) द्वारा किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाला एआईएसएएम एक अधिकार प्राप्त जीओएम है, जिसके पास कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता के बिना, इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। अपने सभी सदस्यों के देश में वापस आने के बाद एआईएसएएम की बैठक होने वाली है। जीतने वाली बोली की घोषणा के बाद, तीन-चार महीने के समय के भीतर पूरी तरह से सौंपने की प्रक्रिया होने की उम्मीद है। केंद्र को 15 सितंबर को एयर इंडिया के विनिवेश के लिए कई वित्तीय बोलियां मिली थीं। हाल ही में, केंद्र ने राष्ट्रीय वाहक से एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को संपत्ति के हस्तांतरण पर कर माफ करने का निर्णय लिया। वित्त वर्ष 2022 के बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सभी प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी, जिसमें एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश भी शामिल है। एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी बेचने का मौजूदा केंद्र सरकार का यह दूसरा प्रयास है। कोरोना महामारी से पहले , एयरलाइन, स्टैंडअलोन आधार पर, 50 से अधिक घरेलू और 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों का संचालन करती थी। इसके अलावा, इसने कोविड महामारी से पहले 120 से अधिक विमानों का संचालन किया। उस अवधि के दौरान, एयरलाइन में 9,000 से अधिक स्थायी और 4,000 संविदा कर्मचारी थे।

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में करदाताओं को 80,086 करोड़ रुपए वापस किए: सीबीडीटी

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अबतक करदाताओं को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लौटाए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह जानकारी दी। सीबीडीटी ने ट्विटर पर लिखा है कि व्यक्तिगत आयकर मद में 47,53,254 करदाताओं को 19,699 करोड़ रुपए और कंपनी कर मामले में 1,63,021 करदाताओं को 60,387 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। बोर्ड ने कहा, ''सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2021 से 27 सितंबर, 2021 के बीच 49.16 लाख से अधिक करदाताओं को 80,086 करोड़ रुपए लौटाए हैं।'' इसमें 20.92 लाख रिफंड आकलन वर्ष 2021-22 के हैं। इसके तहत 1611.45 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं।

पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था : सितंबर में 1.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी संग्रह

नई दिल्ली।

सरकार के जीएसटी संग्रह ने इस वित्तीय वर्ष में अपनी गति बनाए रखी है, क्योंकि आर्थिक सुधार में तेजी आने से कॉपोरेट आय में भी तेजी आ रही है। सितंबर में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,17,010 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। यह पिछले महीने (अगस्त, 2021) के 1,12,020 करोड़ रुपये के संग्रह से भी अधिक है। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस जीएसटी संग्रह में से सीजीएसटी 20,578 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 26,767 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 60,911 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 29,555 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 8,754 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 623 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 28,812 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 24,140 करोड़ रुपये का निपटान किया है। सितंबर 2021 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 49,390 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 50,907 करोड़ रुपये है। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में इस महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 30 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व 20 प्रतिशत अधिक रहा है। सितंबर 2020 में राजस्व, सितंबर 2019 में हुए 91,916 करोड़ रुपये की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो इसी वर्ष की पहली तिमाही में हुए औसत मासिक संग्रह 1.10 लाख करोड़ की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। इसके अलावा, आर्थिक वृद्धि और कर अपवंचना निरोधक गतिविधियों, विशेष रूप से फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ने जीएसटी संग्रह की बढ़ोतरी में योगदान दिया है।

टाटा स्टील ने नेटस्टील होल्डिंग्स में अपनी हिस्सेदारी बेची

नई दिल्ली ।

टाटा स्टील ने कहा कि उसने सिंगापुर की नेटस्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी 17.2 करोड़ डॉलर (करीब 1,275 करोड़ रुपए) में बेच दी है। नेटस्टील, टीएस ग्लोबल होल्डिंग्स (टीएसजीएच) सिंगापुर के अधीनस्थ इस्पात विनिर्माण इकाई है। टीएसजीएच भारत की टाटा स्टील लिमिटेड के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष अनुषंगी है। कंपनी ने कहा कि टाटा स्टील ने सिंगापुर की नेटस्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। इसमें कहा गया कि टाटा स्टील की अप्रत्यक्ष अनुषंगी टीएस ग्लोबल होल्डिंग्स (टीएसजीएच) सिंगापुर ने टॉपटिप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (टॉपटिप) के साथ नैटस्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड में अपनी 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी को 17.2 करोड़ डॉलर (1,275 करोड़ रुपए) के इक्विटी मूल्य पर बेचने के लिए निश्चित समझौता पूरा कर लिया। टाटा स्टील ने कहा कि बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल विदेशी ऋण को कम करने के लिए किया जाएगा।

गेमिंग पीसी में उछाल, मॉनिटर जारी रहने की उम्मीद: रिपोर्ट

सेन फ्रांसिस्को।

गेमिंग पीसी- डेस्कटॉप और नोटबुक दोनों यूनिट शिपमेंट 2020 में 41.3 मिलियन और 2025 में 52.3 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। एक नई रिपोर्ट इसकी जानकारी दी गई है। मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) के अनुसार, गेमिंग मॉनिटर मार्केट के 14.2 मिलियन यूनिट्स से उसी समय सीमा के दौरान 26.4 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आईडीसी के वर्ल्डवाइड क्वार्टरली पीसी मॉनिटर ट्रैकर के शोध प्रबंधक जे चाउ ने एक बयान में कहा, तेजी से सुलभ मूल्य बिंदु और गेमिंग के बाहर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संभालने की क्षमता आने वाले वर्षों में गेमिंग पीसी बाजार के स्वस्थ रहने की उम्मीद के कुछ कारण हैं। ठोस विकास अनुमान मजबूत हालिया रुझानों पर आधारित है। उच्च रसद लागत के साथ-साथ पीसी और डिस्प्ले दोनों को प्रभावित करने वाले घटकों की कमी के बावजूद, 2021 में शिपमेंट तेज बनी हुई है। 2021 की दूसरी तिमाही (2क्यू21) 15.6 मिलियन गेमिंग मॉनिटर और पीसी के संयुक्त शिपमेंट के साथ समाप्त हुई, 2020 में इसी तिमाही की तुलना में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि है। आईडीसी के मोबिलिटी एंड कंज्यूमर डिवाइस ट्रैकर्स के ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट रेयान रीथ ने कहा, गेमिंग मार्केट में 2020 में महामारी की शुरुआत हुई थी और चीजें तेज हो गई थीं क्योंकि ज्यादातर लोग घर पर और स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिता रहे थे। कुल मिलाकर, संयुक्त गेमिंग पीसी और मॉनिटर बाजारों का मूल्य 2020 में 43 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 60 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें 7.4 प्रतिशत की पांच साल की सीएजीआर है। इस वृद्धि के बावजूद, दोनों श्रेणियों में थोड़ा अलग औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) रुझान उभरने की उम्मीद है।

कोलंबो पोर्ट पर टर्मिनल बनाएगा अडाणी ग्रुप

कोलंबो ।

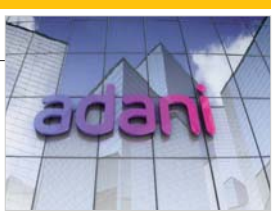

भारत ने चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका में 70 करोड़ डॉलर का एक रणनीतिक डीप सी कंटेनर टर्मिनल का समझौता किया। माना जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को करारा जवाब देने के लिए यह समझौता किया है। द श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और भारत के अडाणी समूह ने यह बड़ा समझौता किया है। यह नया पोर्ट कोलंबो में चीन के बनाए 50 करोड़ डॉलर के चीनी जेटी के पास है। द श्रीलंका पोर्ट्स ने एक बयान जारी करके कहा कि यह समझौता करीब 70 करोड़ डॉलर का है जो श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इसमें कहा गया है कि अडाणी इस बंदरगाह को स्थानीय कंपनी जॉन कील्स के साथ मिलकर बनाएगी। इस टर्मिनल में जॉन कील्स का हिस्सा करीब 34 फीसदी होगा जबकि अडाणी के पास 51 फीसदी की हिस्सेदारी होगी। इस तरह से पूरा पोर्ट अडाणी के नियंत्रण में रहेगा। इसका नाम कोलंबो वेस्ट इंटरनैशनल टर्मिनल रखा गया है। यह नया कंटेनर जेटी करीब 1.4 किलोमीटर लंबा है। यह करीब 20 मीटर गहरा है और यह हर साल 32 लाख कंटेनर हैंडल करेगा। इस प्रॉजेक्ट के पहले चरण में 600 मीटर टर्मिनल बनाया जाएगा और यह दो साल के अंदर पूरा हो जाएगा। करीब 35 साल बाद यह टर्मिनल फिर से श्रीलंका सरकार के अंडर में चला जाएगा। श्रीलंका के रणनीतिक रूप से बेहद अहम कोलंबो बंदरगाह में भारत को अनुमति देने की पिछले कई साल से चल रही थी लेकिन फरवरी में यह समझौता लटक गया।

दरअसल, सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े ट्रेड यूनियन ने भारत को पोर्ट के अंदर आंशिक रूप से बने टर्मिनल को देने का विरोध किया था। श्रीलंका ने पिछले दिनों देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन से फिर 2.2 बिलियन डॉलर का नया कर्ज मांगा था। श्रीलंका पर चीन का पहले से ही अरबों डॉलर का कर्ज है। इसके एवज में उसे अपना हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को सौंपना पड़ा है।

डे नाइट टेस्ट के दूसरे दिन भी बारिश ने डाला खलल, 5 विकेट पर भारत ने बनाए 276 रन

गोल्ड कोस्ट (एजेंसी)।

बिजली चमकने और बारिश के कारण यहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच एकमात्र दिन-रात्रि टेस्ट के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में बाधा उत्पन्न हुई जिससे खेल रोकना पड़ा।

जब खेल रोका गया तब भारतीय टीम ने पांच विकेट गंवाकर 276 रन बना लिये थे।दीप्ति शर्मा 12 रन बनाकर खेल रही थीं जबकि तानिया भाटिया ने अभी खाता नहीं खोला था।

खेल रोके जाने के बाद पिच पर कवर लगा दिया गया और खिलाड़ी भी मैदान से चली गयीं।मौसम विभाग ने इस समय आंधी की भविष्यवाणी की थी और जल्द ही बारिश शुरू हो गयी।इसके बाद मैच् हो ही नहीं पाया और दूसरे दिन के खेल का अंत घोषित करना पड़ा।

भारत ने दूसरे सत्र में दो विकेट गंवाये जिसमें कप्तान मिताली राज (30) और पदार्पण कर रही यास्तिका भाटिया (19) के विकेट शामिल थे।

इससे पहले सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपने शानदार टेस्ट शतक के दौरान कुछ रिकार्ड तोड़े जिससे भारत ने डिनर ब्रेक तक तीन विकेट पर 231 रन बनाये थे।

मंधाना (25 वर्ष) दिन रात्रि टेस्ट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर बनीं और साथ ही आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर खेल के पारंपरिक प्रारूप में सैकड़ा बनाने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनीं।

मंधाना ने करारा ओवल में 22 चौके और एक छक्के की मदद से 216 गेंदों में 127 रन बनाये और आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर दूसरे विकेट के लिये पूनम राउत (36) के साथ 102 रन जोड़े जो भारतीय रिकार्ड है।

शतक जड़कर स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, वसीम जाफर ने 'ऑफसाइड का देवी' बताया

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने क्वींसलैंड के कैरारा में जारी एकमात्र टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन 127 रन की शानदार पारी खेलकर हिन्दुस्तान का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। स्मृति मंधाना ने 127 रन बनाने के लिए 216 गेंदों पर 22 चौके और एक छक्का जड़ा। इसी के साथ ही स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक जड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं।

कोहली भी जड़ चुके हैं शतक

स्मृति मंधाना न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं बल्कि पिंक बॉल टेस्ट में भी... ऐसे में पूरा क्रिकेट जगत उनकी इस पारी की जमकर सराहना कर रहा है। वहीं साल 2019 में विराट कोहली ने कोलकात के ईडन गार्डंस में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए डे नाइट टेस्ट मुकाबले में 136 रन की पारी खेली थी।

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने स्मृति मंधाना की फोटो साझा करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने लिखा कि शतक हमेशा से क्रिकेट में खास होता है और पहला शतक तो और भी ज्यादा। उन्होंने आगे लिखा कि पिंक बॉल टेस्ट में वो भी ऑस्ट्रेलिया में आना बड़ा ही ऐतिहासिक है। ऐसे में शब्द कम पड़ जाते हैं। वहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने स्मृति मंधाना को ऑफसाइड का देवी करार दिया।

ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को अस्पताल से मिली छुट्टी, इंस्टाग्राम पर लिखा ये पोस्ट

रियो दि जिनेरियो (एजेंसी)।

ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को करीब एक महीने बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पेले ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर लिखा ,'' घर लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अलबर्ट आइंस्टीन अस्पताल की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। '' 80 वर्ष के पेले के कोलोन से चार सितंबर को एक गांठ निकाली गई थी।

ऑपरेशन के बाद वह कुछ दिन आईसीयू में थे। अस्पताल ने एक बयान में कहा ,'' मरीज की हालत अब स्थित है और कीमोथेरेपी चलती रहेगी।'' तीन बार के विश्व कप विजेता (1958, 1962, 1970) पेले ने ब्राजील के लिये 92 मैचों में 77 गोल किये हैं।

बड़ा खुलासा: रियो ओलंपिक के 10 बॉक्सिंग मैचों में हुई थी पैसों के लिए हेराफेरी

नई दिल्ली। स्वतंत्र जांच में खुलासा हुआ है कि 2016 रियो ओलिंपिक की मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 10 से अधिक मुकाबलों में 'पैसे' या अन्य 'फायदों' के लिए हेरफेर की गई थी। इस खुलासे के बाद अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) ने आगामी पुरुष विश्व चैंपियनशिप में रैफरी और जज के लिए 'कड़ी' चयन प्रक्रिया का वादा किया है। एआईबीए को मैकलारेन ग्लोबल स्पोर्ट्स सॉल्युशंस (एमजीएसएस) की मुक्केबाजी की स्वतंत्र जांच की पहले चरण की रिपोर्ट मिल गई है।

इसमें खुलासा किया गया है कि रियो में अधिकारियों द्वारा मुकाबलों में हेरफेर की प्रणाली मौजूद थी। कुल मिलाकर दो फाइनल सहित 14 मुकाबले जांच के दायरे में हैं। रिपोर्ट में खेलों में अधिकारियों की संदेहास्पद नियुक्तियों के संदर्भ में किया गया, 'यह सेंटा क्लॉज के भ्रष्ट और शिष्ट के मिथक का पूरी तरह उलट है। भ्रष्ट लोगों को रियो में नियुक्ति दी गई क्योंकि वे इच्छुक थे या दबाव में हेराफेरी के किसी आग्रह का समर्थन करने को तैयार थे जबकि शिष्ट लोगों को बाहर कर दिया गया।'

जांच में खुलासा हुआ है कि रियो के नतीजों को हेराफेरी का षड्यंत्र लंदन ओलिंपिक 2012 से पहले भी रचा गया और 2016 टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग टूर्नामेंटों के दौरान इसका ट्रायल किया गया। इसमें कहा गया, 'पैसे और एआईबीए से फायदे के लिए मुकाबलों में हेरफेर की गई या राष्ट्रीय महासंघों और उनकी ओलिंपिक समितियों का आभार जताने के लिए और कुछ मौकों पर प्रतियोगिता के मेजबान की उसके वित्तीय समर्थन और राजनीतिक समर्थन के लिए।'

इसमें कहा गया, 'आज तक की जांच में निष्कर्ष निकलता है कि इस तरह की हेराफेरी में कई मौकों पर छह अंक की मोटी धनराशि जुड़ी होती थी। हेराफेरी की प्रणाली भ्रष्ट रैफरी और जज तथा ड्रॉ आयोग से जुड़ी थी।' एआईबीए ने विस्तृत कार्रवाई और रैफरी तथा जजों की नियुक्ति के लिए कड़ी प्रक्रिया का वादा किया है। अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति से दोबारा मान्यता हासिल करने का प्रयास कर रहे एआईबीए ने कहा, 'एआईबीए रियो 2016 मुक्केबाजी टूर्नामेंट की जांच के नतीजों से चिंतित है और पुष्टि करता है कि विस्तृत सुधारवादी कदम उठाए जाएंगे जिससे कि मौजूदा एआईबीए प्रतियोगिताओं की अखंडता बनी रहे।'

गरीबी में पंजाब का आटा गीला कर गए गेल, टी-20 विश्वकप के लिए छोड़ा आईपीएल 2021

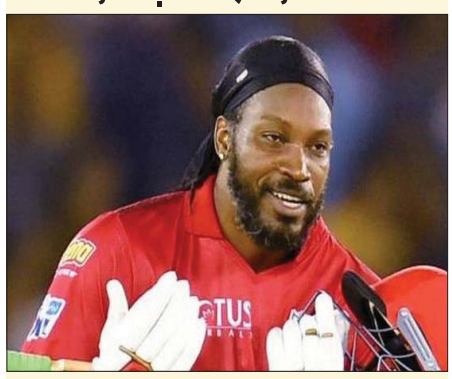

नई दिल्ली। पंजाब किंग्स का हाल वैसे भी काफी खराब चल रहा था अब क्रिस गेल ने एक और झटका प्रीति जिंटा की टीम को दे दिया है। वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स का बायोबबल छोड़ दिया है।

क्रिकेट के यूनीवर्स बॉस और पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल यहां जारी आईपीएल के दूसरे चरण के बीच बायो-बबल थकान का हवाला देते हुए आईपीएल से बाहर हो गए हैं। पंजाब किंग्स ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'बायो-बबल थकान के कारण क्रिस गेल आईपीएल बायो-बबल छोड़ रहे हैं। सीपीएल (कैरिबियाई प्रीमियर लीग) बायो-बबल और फिर आईपीएल बायो-बबल का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने टी-20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज का प्रतिनिधित्व करने से पहले दुबई में खुद को मानसिक रूप से तरोताजा करने की इच्छा जताई है।' उल्लेखनीय है कि गेल ने खुद भी आईसीसी टी-20 विश्व कप से पहले खुद को मानसिक रूप से तरोताजा रखने की बात कही है।

गेल ने पंजाब किंग्स द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा, 'पिछले कुछ महीनों में मैं क्रिकेट वेस्ट इंडीज बायो-बबल, सीपीएल बायो-बबल और उसके बाद आईपीएल बायो-बबल का हिस्सा रहा हूं, लेकिन अब मैं खुद को मानसिक रूप से तरोताजा करना चाहता हूं। मैं टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की मदद करने पर फिर से ध्यान देना चाहता हूं और दुबई में एक ब्रेक लेना चाहता हूं। मुझे समय देने के लिए पंजाब किंग्स को मेरा धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं और उम्मीदें हमेशा टीम के साथ हैं। आने वाले मैचों के लिए शुभकामनाएं।'

पंजाब किंग्स के क्रिकेट संचालन निदेशक अनिल कुंबले ने कहा, 'मैंने क्रिस के खिलाफ खेला है और उन्हें पंजाब किंग्स में कोचिंग दी है और मैं काफी वर्षों से उन्हें जानता हूं कि वह हमेशा एक पूरे पेशेवर रहे हैं। हम एक टीम के रूप में उनके फैसले का सम्मान करते हैं। गेल अपने वेस्ट इंडीज टीम के साथियों के साथ जुड़ने से पहले दुबई में रहेंगे।' वह सीपीएल 2021 की समाप्ति के बाद सीधे वहां से आईपीएल बायो-बबल में शामिल हुए थे।

वक्त बदला लेकिन धोनी नहीं, छक्का मारकर गेंद को स्टेडियम की छत पर पहुंचाया

नई दिल्ली (एजेंसी)।

चेन्नई सुपरकिंग्स गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में पहुंच गई। इस मैच में धोनी ने सिद्धार्थ कौल की गेंद पर छक्का मारकर चेन्नई को जीत दिलाई। इस छक्के से धोनी ने एक बार फिर क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने तब लगाया जब टीम को 3 गेंदो में 2 रनों की जरूरत थी। अंतिम गेंद में धोनी छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस मैच में भी धोनी ने एक ऐसा गगनचुंबी छक्का मारा जो शारजाह के स्टेडियम की छत पर जा पहुंचा। इस छक्के से धोनी से साबित कर दिया की वक्त भले ही बदल गया हो लेकिन धोनी वही है। कहने को तो यह इस टूर्नामेंट में धोनी का दूसरा ही छक्का था लेकिन इस छक्के ने बड़ा काम कर दिया। छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चेन्नई ने हैदराबाद को 20 ओवर में सात विकेट पर 134 रन पर रोका और 19.4 ओवर में चार विकेट पर 139 रन बनाकर जीत हासिल की। 19 सितंबर से चेन्नई सुपर किंग्स जब से संयुक्त अरब अमीरात आयी है तब से एक भी मैच नहीं हारी है।

'हो कर रहेगी एशेज', कंगारू कप्तान ने केविन पीटरसन को दिया दो टूक जवाब

मेलबर्न (एजेंसी)।

आस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि अगर पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने कोविड-19 पाबंदियों के कारण एशेज के लिये दौरा करने से इनकार कर दिया, तब भी दोनों देशों के बीच यह टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जायेगी।

एशेज को लेकर काफी अटकलें लगायी जा रही हैं क्योंकि इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों ने आस्ट्रेलिया में सख्त कोविड-19 पाबंदियों के बीच परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करने पर चिंता व्यक्त की हैं जिसमें टेस्ट कप्तान जो रूट भी शामिल हैं और यहां तक कि कुछ तो दौरे से हटने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन पेन ने 'सेन होबार्ट' से कहा, ''एशेज आयोजित की जायेगी। पहला टेस्ट आठ दिसंबर से शुरू होगा - भले ही जो (रूट) यहां आये या नहीं।'

उन्होंने कहा, 'वे सभी आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वे खुद को सर्वश्रेष्ठ संभावित परिस्थितियों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर में हम सब भी ऐसा ही कर रहे हैं।' इससे पहले रूट और इंग्लैंड की टीम के अन्य सदस्यों ने दौरे पर संशय व्यक्त किया था जिसमें उन्होंने कड़ी पाबंदियों में रहने की संभावना के बीच 'बायो-बबल की थकान' का हवाला दिया था।

पेन ने कहा, 'उनके पास विकल्प है कि वे यहां आने के लिये फ्लाइट में बैठना चाहते हैं या नहीं।' उन्होंने कहा, 'कोई भी किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को यहां आने के लिये बाध्य नहीं कर रहा है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, यह उसकी खूबसूरती है कि आपके पास विकल्प होता है। अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आओ।' पेन ने साथ ही इंग्लैंड के पूर्व स्टार केविन पीटरसन से कहा कि खिलाड़ियों को अपना फैसला खुद करने दें कि वे एशेज में खेलना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा, 'वह (पीटरसन) हर चीज का विशेषज्ञ है, इसमें कोई शक नहीं है।' पेन ने कहा, 'केव, इस पर फैसला खिलाड़ियों पर छोड़ दीजिये, उन्हें बोलने दीजिये। हमने एक भी इंग्लैंड के खिलाड़ी को यह कहते हुए नहीं सुना कि वे नहीं आ रहे हैं।'

पीटरसन ने हाल में ट्विटर पर आस्ट्रेलिया के पृथकवास नियमों की आलोचना की थी और कहा था कि खिलाड़ी बायो-बबल में रहकर थक गये हैं और साथ ही उन्होंने एशेज से पहले आस्ट्रेलिया में इन 'पृथकवास के नियमों' को हटाने की बात भी की थी।

उल्लेखनीय है कि दबी हुई नस के चलते डिस्क के बाहर आने से पेन के गर्दन और बाएं हाथ में दर्द हो रहा था, जिसके चलते इस हफ्ते उनकी सर्जरी की गई है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सर्जन्स ने उनके गले में एक छेद किया है। इंग्लैंड ने एशेज के दौरान होने वाली परिस्थितियों में खिलाड़ियों के रहने को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जिससे श्रृंखला के योजना के अनुसार आगे बढ़ने पर संदेह पैदा हो गया है, लेकिन पेन का मानना है कि हालात कहीं भी उतने खराब नहीं होंगे जितना कि मेहमान इंग्लैंड को डर है।

आईपीएल 2021 के प्लेआफ की रेस से बाहर हुई ये टीम, कप्तान बदलने से भी नहीं मिला फायदा

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल के 14वें सीजन के प्लेआफ में पहुंचने वाली एक टीम की घोषणा हो गई है, जबकि एक टीम प्लेआफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। आइपीएल 2021 के प्लेआफ के लिए क्वालीफाइ करने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, जबकि नाकआउट की रेस से नराइजर्स हैदराबाद नाकआउट हो गई है। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद मैनेजमेंट की एक भी चाल कारगर साबित नहीं हुई।

दरअसल, पिछले साल आइपीएल की अंकतालिका में डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे पायदान पर थी और टीम क्वालीफायर्स खेली थी। एलिमिनेटर मैच जीतने के बाद टीम को क्वालीफायर 2 में हार मिली थी और टीम फाइनल में प्रवेश नहीं कर सकी थी। वहीं, 2021 के सीजन में टीम को खराब शुरुआत मिली और टीम पहले 3 मैच हार गई। चौथे मैच में टीम को जीत मिली, लेकिन डेविड वार्नर की कप्तानी में स्त्रा अगले दो मैच और हार गई।

आईपीएल 2021 के सीजन में हैदराबाद अपने पहले 6 मैचों में सिर्फ एक मैच में जीत मिली। इस प्रदर्शन की वजह से मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी ने डेविड वार्नर से कप्तानी छीन ली और केन विलियमसन को टीम की कमान सौंप दी। हालांकि, केन विलियमसन की कप्तानी में भी टीम पहला मैच हार गई। बाद में कोरोना के कारण भारत में खेला जा रहा आइपीएल का 14वां सीजन स्थगित हो गया। सितंबर में यूएई के मैदान पर फिर से आइपीएल शुरू हुआ, लेकिन टीम की किस्मत नहीं बदली।

कांस्य पदक से चूके दीपिका और अतनु, भारत की झोली रही खाली

यांकटन (अमेरिका) (एजेंसी)।

भारत के सितारा तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी कांस्य पदक के मुकाबले हार गए जिससे भारत को विश्व कप फाइनल से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भारतीय रिकर्व कोच की गैर मौजूदगी में इस जोड़ी को सर्द मौसम में खेले गए मुकाबले में काफी दिक्कतें आई। दास को मौजूदा ओलंपिक चैम्पियन तुर्की के मेटे गाजोज ने एकतरफा मुकाबले में 6 . 0 (27 . 29, 26 . 27, 28 . 30) से हराया। वहीं दुनिया की दूसरे नंबर की तीरंदाज और दास की पत्नी दीपिका को ओलंपिक टीम कांस्य पदक विजेता मिशेले क्रोप्पेन ने शूटआफ में मात दी। आठवीं बार फाइनल खेल रही दीपिका 5 . 6 (6 . 9) से हारी। तोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद वह पहला टूर्नामेंट खेल रही थी। तीन बार की ओलंपियन दीपिका जर्मन प्रतिद्वंद्वी के सामने परफेक्ट 30 स्कोर नहीं कर सकी।

मिशेले ने पहले दो सेट में पूरे 30 . 30 अंक बनाये जबकि तीसरे सेट में दोनों ने 28 का स्कोर किया। चौथा सेट दीपिका ने जीता। पांचवें सेट में 28 स्कोर करके दीपिका ने मुकाबले को शूटआफ तक खिंचा लेकिन शूटआफ में अपेक्षा के अनुरूप नहीं खेल सकी। दीपिका ने क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक टीम रजत पदक विजेता रूस की स्वेतलाना गोंबोएवा को 6 . 4 से हराया था। सेमीफाइनल में वह तोक्यो ओलंपिक दोहरी रजत पदक विजेता रूस की एलेना ओसिपोवा से हार गई थी। वहीं दास ने जर्मनी के मैक्सीमिलन वेकम्यूलर को हराकर शुरूआत की लेकिन अमेरिका के ब्राडी एलिसन से हार गए।

सूरत : वैक्सीन के दोनों डोज लिया होगा तो गरबा खेलने दिया जाएगा

सूरत।

सूरत शहर में कोरोना केस की संख्या में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर सील किए गए दो अपार्टमेंट में फिर से तीन बच्चे कोरोना संक्रमित होने पर पालिका द्वारा कोन्टेक ट्रेसिंग और टेस्टिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पिछले दो सप्ताह के दौरान रांदेर और अठवा जोन क्षेत्र में पॉजिटिव केस सामने आने पर महानगरपालिका तरफ से १८०० एक्टिव सर्वेलंस वर्करों को काम में लगाया गया है। दूसरी तरफ आगामी नवरात्रि के पर्व को लेकर आयोजित हो रहे शेरी-गरबा के तहत सूरत महानगरपालिका द्वारा विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज और दूसरा डोज लिया होगा, ऐसे लोगों को ही शेरी गरबा या सोसाइटी में आयोजित होने वाला गरबा में हिस्सा लेने दिया जाएगा। शहर में एक के बाद एक सोसाइटियों में कोरोना के केस दर्ज हो रहे हैं। जिसे लेकर हेल्थ विभाग सक्रिय हो गया है। राज्य सरकार की छूट के बाद शादी प्रसंग और सार्वजनिक मेले में गये लोग अब कोरोना संक्रमित हो रहे है। जिसमें सूरत के पीपलोद और अठवा क्षेत्र में सप्ताह पहले

कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से दो अपार्टमेंट को सील किया गया है। जिसमें पीपलोद में स्थित आविष्कार अपार्टमेंट से दो और मेघ मयुर अपार्टमेंट से और एक केस कोरोना पॉजिटिव मिले है। जो केस सामने आये है इसमें तीन बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। जिसके बाद पालिका द्वारा कोन्टेक ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कामकाज में तेजी लाई गई है। सूरत के अठवा और रांदेर जोन में कोरोना केस में फिर से १०० फीसदी वृद्धि हुई है। जिसके लिए पालिका द्वारा १८०० सर्वेलंस वर्करों से काम लिया जा रहा है। आगामी दिनों में नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है।

दो वर्ष के बच्चे का खेलते हुए ८वीं मंजिल से गिरने पर मौत

सूरत।

डांस करते करते भूल से गले में फांसी लग जाना, खेलते खेलते बाल्कनी से नीचे गिर जाने से मामले सूरत में सामने आ चुके है। यह सभी मामले मां-पिता के लिए चेतावनी समान है। सूरत में और एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसमें दो वर्ष का बच्चा खेलते-खेलते ८वीं मंजिल से नीचे गिर गया। यह पूरी घटना अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह मामले में कतारगाम पुलिस ने दुर्घटना से मौत का अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला सूरत शहर के कतारगाम क्षेत्र का है। जिसमें लक्ष्मी रेसिडेंसी नाम के अपार्टमेंट से एक दो वर्ष का बच्चा खेलते-खेलते नीचे गिर गया। ८वीं मंजिल से नीचे गिरने पर बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। वास्तव में यह बच्चा अपने फ्लैट के आगे के हिस्से में पैसेज आया था वहां खेल रहा था। इस दौरान यह पैसेज में लगाई गई ग्रील से नीचे गिर गया। दो वर्ष के बच्चे का इस तरीके से मौत होने से सनसनी मच गई है। दूसरी तरफ परिवार में शोक की लहर फैल गई। यह मामला सीसीटीवी में कैद लक्ष्मी रेसिडेंसी अपार्टमेंट में हुई यह घटना वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सामने आये सीसीटीवी फूटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा अपने घर के बाहर के पैसेज में खेल रहा है। इस दौरान वह वहां लगी ग्रील पर चढ़ना-उतरता है। एक समय वह ग्रील से सिर बाहर निकालता है। यह दौरान अपने शरीर का बेलेन्स बिगड़ जाता है और इसका पैर ऊंचा हो जाता है। दूसरी तरफ बच्चा ग्रील से नीचे गिर जाता है। सूरत का यह मामला ऐसे सभी मां-पिता के लिए चेतावनी समान है, जिनके छोटे बच्चे है। अधिकतर सभी बहुमंजिला अपार्टमेंट में इस प्रकार की पेसेज दी जाती है। अधिकतर वहां

सीढ़ी के सामने के बगल में खुली जगह होती है और इसमें सेफ्टी के लिए ग्रील लगाया जाता है। इस मामले में सेफ्टी ग्रील की ऊंचाई कम थी तथा इसमें से बच्चा चला जाता है इतनी जगह थी। अधिकतर बच्चे शाम के समय फ्लैट के बाहर इस पेसेज में खेलते है।

शिक्षक ने चालू क्लास में विद्यार्थिनी के साथ छेड़छाड़ किया

गुस्सा हुई दादी, नेहा और अपने पिता के साथ स्कूल में पहुंची थी, दूसरी तरफ शिक्षक स्कूल में नहीं आया था

अहमदाबाद।

सूरत के कापोद्रा अश्वनीकुमार रोडनी जगदगुरू श्री वल्लभाचार्य स्कूल के कक्षा-७ में पढ़ाई करती १२ वर्षीय किशोरी की पिछले एक महीने से चालू क्लास में छेड़छाड़ करने पर विज्ञान शिक्षक की कापोद्रा पुलिस ने अपराध दर्ज करके गिरफ्तार किया है। मूल सौराष्ट्र के निवासी और सूरत में अश्वनीकुमार रोड में रहते परिवार की १२ वर्षीय बेटी कापोद्रा अश्वनीकुमार रोडनी जगदगुरू श्री वल्लभाचार्य स्कूल के कक्षा-७ में पढ़ाई करती है। एक महीने पहले स्कूल से दोपहर में घर पर वापस आयी नेहा ने अपनी दादी को कहा था कि इसकी स्कूल में विज्ञान पढ़ाते सर नीरव वैष्णव चालू क्लास में इसके साथ छेड़छाड़ करते है। दादी को लगा था कि नेहा स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाती है। इसी वजह से उसने बात को ध्यान में नहीं लिया था। हालांकि इसके बाद भी नेहा अपने सर की शिकायत करती हो दादी ने दूसरे दिन स्कूल में आकर मैडम को बात करने के लिए कहा था। लेकिन उस समय में नेहा ने मैडम को बात नहीं करने और अब इसके बाद सर ऐसा करेंगे तो आपको कहूंगा यह कहा था। दो दिन के बाद दादी अपने देवर के श्राद्ध के मौके पर अपने वतन गई थी। इस दौरान गत दिन नेहा के पिता ने उनको फोन करके जानकारी दी थी कि नेहा स्कूल में जाने से मना करती

थी। उन्होंने इस मामले में पूछा तो सर छेड़छाड़ करता है ऐसी बात करते है और इसकी जानकारी दादी को दी है यह भी कहा था। इसी वजह से दादी ने सूरत आकर नेहा को पूछा तो नीरव सर ने फिर से गंदी हरकत की थी यह कहा था। इस बात से गुस्से हुई दादी, नेहा और इसके पिता के साथ पहुंचे थे। दूसरी तरफ नीरव वैष्णव सर स्कूल में नहीं आये था। आचार्य ने भी सर का बचाव किया था कि इसे हमने निकाल दिया है। इसी वजह से दादी ने इस मामले में कापोद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने छेड़छाड़ का अपराध दर्ज करके शिक्षक नीरव वैष्णव को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल द्वारा गांधी जयंती के पर्व पर ऑनलाइन सेलिब्रेट किया गया

सूरत।

शुक्रवार के दिन दी रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल अडाजन और रेडिएंट प्री स्कूल द्वारा प्री प्राइमरी विभाग के बच्चों को गांधी जी और उनकी जीवनशैली की जानकारी देने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर ऑनलाइन सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों ने विविध तरह की प्रवृतियां जैसे कि कागज से चश्मा, माचिस की तिल्ली से रेंटियो और स्वच्छता अभियान के लिए सोसाइटी के बच्चों द्वारा रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद बच्चों ने गांधी जी की पोशाक पहनी और उनकी जीवन शैली पर भाषण दिया। इस गतिविधि ने बच्चों के माता पिता और परिवार में बहुत उत्साह पैदा किया और परिवार के बुजुर्गों ने उत्साह पूर्वक गांधी दर्शन और उनकी आजादी की कहानी सुनाई है, जिसे सुनकर बच्चे खूब खुश हुए।

सूरत में डायलिसिस सेंटर का सीलिंग टूटकर बेड पर गिरा

आसपास के बेड पर मौजूद मरीज एकदम से घबरा गए, सूत्रों का कहना कि उस बेड पर कुछ ही देर में मरीज आने वाला था

सूरत।

सूरत शहर के सिविल अस्पताल के जी-० वार्ड में स्थित डायलिसिस सेंटर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल, डायलिसिस सेंटर की सीलिंग अचानक से गिर पड़ी। गनीमत रही कि जहां सीलिंग गिरी वहां दो बेड लगे हुए थे, पर कोई मरीज उस वक्त नहीं था, वरना कुछ भी हो सकता था। आसपास के बेड पर मौजूद मरीज एकदम से घबरा गए। सूत्रों का कहना कि उस बेड पर कुछ ही देर में मरीज आने वाला था। उस वार्ड की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां डॉक्टर बैठते हैं, वहां की सीलिंग गिरने की हालत में है, पर सिविल प्रशासन शायद किसी हादसे के इंतजार में ही बैठा हुआ है। जर्जर भवन व लॉबी के विभिन्न वार्डों में स्लैब से बारिश का पानी टपकने लगता है। इससे मरीजों व उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिविल प्रशासन की सुस्ती का आलम यह है कि हादसे के १२ घंटे बीत जाने के बाद भी मरम्मत करना तो दूर कोई सुध भी नहीं लिया गया। इधर, मरीज डरे-सहमे इलाज ले रहे हैं। वहीं, कर्मचारी भी किसी भी वक्त स्लैब गिरने की आशंका के बीच डरकर काम कर रहे हैं। अभी वार्ड में ५ से ६ मरीजों का इलाज चल रहा है।

राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, रात्रि जागरण कर वोट जुटाने की कोशिश

अहमदाबाद।

गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव के अंतिम दौर के प्रचार में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल शुक्रवार दोपहर गांधीनगर में रोड शो करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी गत दिनों रोड शो किया था। गांधीनगर में रात्रि जागरण के जरिए वोट जुटाने की भी पुरजोर कोशिश की गई। गुजरात में वर्ष २०२१ की शुरुआत फरवरी-मार्च में पंचायत व निकाय चुनाव से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी व भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन किया। राज्य में मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार बदले जाने के बाद भाजपा का यह पहला चुनाव है लेकिन इसे सभी प्रमुख दलों ने नाक की लड़ाई बना ली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर की महानगरपालिका पर हाल भाजपा का कब्जा है लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की ओर से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। ३ अक्टूबर को गांधी नगर महानगर पालिका का चुनाव होगा इससे पहले भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी अलग-अलग तरीकों से प्रचार करते हुए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने गांधीनगर में गत दिनों एक लोक डायरा जागरण कार्यक्रम रखा था जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। इसके बाद भाजपा ने भी ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाल ही गांधीनगर में एक रोड शो करके गए हैं। शुक्रवार को गांधीनगर महानगरपालिका का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता घर-घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटील शुक्रवार दोपहर गांधीनगर में एक रोड शो भी करने वाले हैं। गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव परिणाम ५ अक्टूबर को घोषित होंगे। इसे जीतने के लिए तीनों ही प्रमुख दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार बनने के बाद भाजपा का यह पहला चुनाव उसके लिए कसौटी बन गया है। आम आदमी पार्टी ने सूरत के बाद गांधीनगर में जोरदार जनसंपर्क कर अपने लिए जमीन तैयार करने का प्रयास किया है जिसके चलते भाजपा कांग्रेस दोनों को यह चुनाव जीतने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा। भाजपा की सरकार में करीब एक दर्जन मंत्री इस चुनाव प्रचार में लगाए गए ११ वार्ड के ४४ सीटों के लिए ३ अक्टूबर को चुनाव होगा। सरकार के मंत्री जहां हर एक वार्ड में मौजूद रहकर जनसंपर्क कर रहे हैं,

बापू का भजन 'वैष्णव जन' कश्मीरी भाषा में पहली बार गूंजेगा

अहमदाबाद।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती २ अक्टूबर पर पहली बार साबरमती आश्रम-अहमदाबाद में कश्मीरी भाषा में बापू के प्रिय भजन 'वैष्णवजन तो तेने रे कहिए ...' के बोल गूंजेंगे। दरअसल, विख्यात सूफी कश्मीरी गायक गुलजार अहदम गनाई कश्मीरी भाषा में पहली बार बापू के इस प्रिय भजन की सार्जवनिक प्रस्तुति साबरमती आश्रम में देंगे। साथ ही इसी दिन बापू की आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' के कश्मीरी और बोडो भाषा संस्करण का लोकार्पण भी होगा। सुधीन्द्र कुलकर्णी और राजेन्द्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधीजी द्वारा स्थापित नवजीवन ट्रस्ट ने 'सत्य के प्रयोग' के कश्मीरी और बोडो संस्करण तैयार किए हैं। इन दो संस्करणों के साथ नवजीवन द्वारा बापू की आत्मकथा १८ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी। नवजीवन ट्रस्ट के न्यासी कपिल रावल ने बताया कि कश्मीर और असम हिंसा से जूझ रहे हैं। बापू के विचारों को वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इन राज्यों की बोली-भाषा में बापू की आत्मकथा इस दिशा में पहला कदम है। २०१३ में कश्मीरी भाषा में 'सत्य के प्रयोग' का प्रकाशन करने का निर्णय लिया था। इसकी जानकारी मिलने पर कश्मीरी प्रोफेसर गुलामनबी खयाल ने हमें सूचित किया कि उनके पास वर्ष १९७४ में प्रकाशित हुई आत्मकथा की प्रति है, जो आउट ऑफ प्रिंट है। हम वह प्रति लेकर इसका पुनः प्रकाशन कर रहे हैं। कश्मीर के पद्मश्री अख्तर मोहियुद्दीन ने तब आत्मकथा का अनुवाद किया था। कश्मीर स्टेट कल्चरल अकादमी ने इसका प्रकाशन किया था। नवजीवन ट्रस्ट ने अब तक १६ भारतीय भाषाओं में बापू की आत्म कथा 'सत्य के प्रयोग' प्रकाशित की है। इन सभी भाषाओं में कुल ५८.९० लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। सर्वाधिक ८.४२ लाख प्रतियां मलयालम भाषा में बिकी।

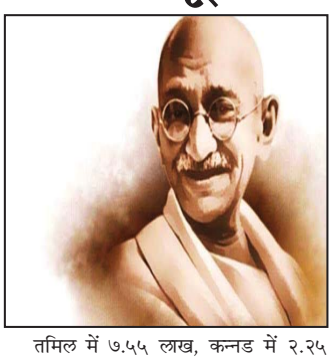

तमिल में ७.५५ लाख, कन्नड में २.२५ लाख और गुजराती में ६.८६ लाख प्रतियां बिकीं। अब कश्मीरी और बोडो भाषा में भी प्रकाशन हो रहा है। गांधी जयंती पर विश्व ग्राम संस्था ने 'नर सिंह से गांधी तक' थीम निर्धारित की है। 'वैष्णवजन' भजन थीम के केन्द्र में है। इस थीम पर पूरे राज्य में ६ अक्टूबर तक कार्यक्रम होगा। ये अहमदाबाद से शुरू होकर नरसिंह मेहता के जूनागढ़ में विराम लेगा।

पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी को गुजरात हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत

अहमदाबाद।

गुजशत के अमित जेठवा हत्याकांड मामले में सीबीआइ अदालत के आदेश पश आजीवन काशवास की सजा काट रहे पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी को गुजशत उच्च न्यायालय ने एक लाख रुपये के बांड पश सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट के फैसले को तर्कसंगत नहीं मानते हुए कहा कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से जुड़ा है। प्रथम द्रष्टया सजा का फैसला गलत लगता है। गुजशत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश परेश उपाध्याय व न्यायाधीश एसी जोशी ने आरटीआइ एक्टिविस्ट अमित जेठवा की हत्या मामले में आजीवन काशवास की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी को सशर्त जमानत पश छोड़ते हुए कहा कि सीबीआइ की विशेष अदालत का फैसला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पश है, इसलिए इसे पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता है। घटना का सिलसिलेवार अध्ययन करने पर यह फैसला गलत प्रतीत होता है। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद को एक लाख के निजी बांड व इतनी ही शशि के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है, लेकिन उनकी विदेश यात्रा पश शेक रहेगी। सोलंकी को पासपोर्ट अदालत में जमा कराने का भी आदेश दिया है। पूर्व सांसद सोलंकी को सीबीआई ने ११ जुलाई, २०१९ को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सोलंकी सहित सात को सजा सुनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि जूनागढ़ में गीर नेचर यूथ क्लब का गठन कर गीर जंगल में होने वाले अवैध खनन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते थे। अमित जेठवा ने शज्य में आरटीआइ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान कायम कर ली थी। २० जुलाई, २०१० को अमित की गुजशत उच्च न्यायालय भवन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वे सत्यमेव काम्पलेक्स में अपने वकील से मिलकर निकल रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों में से एक ने उन्हें गोली मार दी थी। गुजशत पुलिस ने इस मामले में पुलिस कांस्टेबल बहादुर सिंह वाढेर, शार्प शूटर शैलेष पंड्या व पंचन शिल्वा की धरपकड़ कर ली थी। इसके बाद सितंबर, २०१० में पूर्व सांसद के भाई शिवा सोलंकी को पकड़ा गया। उच्च न्यायालय के आदेश पर बाद में नवंबर, २०१३ में इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। सीबीआइ ने ११ जुलाई, २०१९ को पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में १९० गवाह बने थे, जिनमें से १०५ अपने बयानों से मुकर गए थे। गवाहों को धमकाने के मामले सामने आने के बाद गुजशत उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच नए सिरे से कराने के आदेश दिए थे। उच्चतम न्यायालय ने फैसले में सुधार करते हुए केवल २४ गवाहों के बयानों का परीक्षण का निर्देश जारी कर दिया था।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादक: संजय रमाशंकर मिश्रा द्वारा ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सुरत (गुजरात) प्रिन्टर्स- भूनेश्वरा प्रिन्टर्स, प्लाट नं. 29, परमानन्द इण्डस्ट्रीयल सोसायटी, चौकसी मील के पास, उधना मगदल्ला रोड़ (गुजरात) से मुद्रित एवं ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सूरत (गुजरात) से प्रकाशित। कार्यालय फोन: 0261-2274271, (न्यायिक क्षेत्र सूरत रहेगा)